सुविचार

घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ वक्त करता है।

–गौतम बुद्ध

Daily

THE PHOTON NEWS

सच के हक में...

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Thursday, 21 May 2026 ● Year : 05 ● Issue : 125 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Rashmika Mandanna Calls Cocktail...

12

SHARE

सेंसेक्स	:	75,318.39
निफ्टी	:	23,659.00

SARAFA

सोना	:	14,665
चांदी	:	285.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

सारंडा में सक्रिय रहे 25 माओवादी आज एक साथ करेंगे आत्मसमर्पण

RANCHI : झारखंड पुलिस की उपलब्धियों के लिए गुरुवार (21 मई) ऐतिहासिक दिन साबित होगा। इस दिन सारंडा में सक्रिय 25 माओवादी एक साथ आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इनमें 10 महिला माओवादी भी हैं। झारखंड में यह अबतक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होगा। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से माओवादी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। वे लगातार पुलिस की गोलियों के शिकार हो रहे हैं। सारंडा में भी उनका ठिकाना सुरक्षित नहीं बचा है। पुलिस ने उन्हें घेर रखा है। इसलिए आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में 25 माओवादी हथियार डालने जा हे हैं।

पूरी खबर पेज 04 पर

पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

HARIDWAR : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूरी को बुधवार को हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका सोमवार को देहरादून में निधन हो गया था। उनके पुत्र मनीष खंडूरी ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। स्वर्गीय खंडूड़ी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर वर्ग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार से पूर्व सेना व पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दिवंगत नेता को अंतिम सलामी दी। श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का जीवन सादगी, अनुशासन और ईमानदारी का उदाहरण रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सेना अधिकारी के रूप में हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया।

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर हाईलेवल मीटिंग

NEW DELHI : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) पुनर्परीक्षा की निष्पक्ष और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परीक्षा के दौरान कड़ी सतर्कता और चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक ने भी हिस्सा लिया। बैठक में परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संभावित कमजोरियों की पहचान कर समय रहते निवारक और सुधारात्मक कदम उठाने पर चर्चा हुई। इसके समानांतर शिक्षा मंत्री ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की।

झारखंड सहित देशभर में बंद रहे 15 लाख से अधिक मेडिकल स्टोर

सरकारी और निजी अस्पतालों की फार्मेसी दुकानों को बंद से रखा गया था अलग

झारखंड में बंद रहीं 18 हजार से ज्यादा दुकानें, रांची में दिखा व्यापक असर

PHOTON NEWS RANCHI/DELHI : बुधवार को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और झारखंड केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर झारखंड सहित देश भर के 15 लाख से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहे। झारखंड में इस आह्वान के तहत 18 हजार से अधिक थोक और खुदरा दवा की दुकानें नहीं खुलीं। इसका राज्य सहित अन्य शहरों में व्यापक असर दिखा। सरकारी और निजी अस्पतालों की फामेर्सी दुकानों को बंद से अलग रखा गया था। हालांकि झारखंड के सरकारी और निजी अस्पतालों की फामेर्सी दुकानों को बंद से अलग रखा गया है। इस संबंध में झारखंड ड्रगिस्ट्स एंड केमिस्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय सचिव संजीव बनर्जी ने बताया कि मुख्यतः तीन मांगों को लेकर दवा दुकानदारों की राष्ट्रव्यापी बंद झारखंड में बंद पूरी तरह सफल है।

- ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स और झारखंड केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने किया था आह्वान
- ऑनलाइन फार्मेसी के अनियंत्रित विस्तार व कॉरपोरेट कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति का किया गया विरोध
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त सत्यापन के कर रहे दवाओं की बिक्री
- एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार किया जा रहा उपयोग

डीप डिस्काउंटिंग का भी हो रहा विरोध

संजीव ने बताया कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन फामेर्सी के अनियंत्रित विस्तार और कॉरपोरेट कंपनियों की कथित शोषणकारी मूल्य निर्धारण नीति के खिलाफ आवाज उठाना है। संजीव बनर्जी ने कहा कि कोरोना काल में दवाओं को घर-घर पहुंचाने का निर्देश केंद्र की सरकार द्वारा दिया गया था, तब एसोसिएशन ने उस वक्त के हालात देखते हुए सरकार के निर्णय का स्वागत किया था, लेकिन वह व्यवस्था आज भी चली आ रही है और कई तरह की गड़बड़ी इस व्यवस्था के तहत हो रही है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त सत्यापन के दवाइयों की बिक्री कर रहे हैं, जिससे एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार उपयोग हो रहा है। साथ ही एआई आधारित फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं की उपलब्धता बढ़ रही है, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) का खतरा बढ़ा है। इसके अलावा बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा डीप डिस्काउंटिंग के जरिए बाजार संतुलन बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। संजीव बनर्जी ने कहा कि आवश्यक दवाओं की कीमतें पहले से ही सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। बावजूद इसके कॉरपोरेट कंपनियां अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं, जिससे छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के केमिस्टों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार को जीएसआर 220 ई को ऑनलाइन दवा बेचने का अधिकार देती है। इसे रद्द किया जाए, क्योंकि इससे नकली दवाएं भी जनता के बीच खपाई जाती हैं। बिना नियमों के चल रही ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से मोहल्ले की छोटी दुकानों को नुकसान हो रहा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चार सांसदों ने उनके खिलाफ की वोटिंग

ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी संसद से पास

NEW DELHI @ PTI : बुधवार को अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। तीन रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ। इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। यह वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। वे कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं, बल्कि संसद के पास होना चाहिए।

मतदान में शामिल नहीं हुए तीन रिपब्लिकन सांसद

वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लेकर आए प्रस्ताव

प्रस्ताव को वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लेकर आए हैं। बहस के दौरान उन्होंने कहा कि अभी जब युद्धविराम की बात हो रही है, तब ट्रंप को संसद के सामने आकर अपनी रणनीति बतानी चाहिए। डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन ने कहा कि युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिकी सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों के तहत कार्रवाई की है। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है, कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है या फिर सेना की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगनी होती है।

दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हवाई हमले

दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, इजराइली विमानों ने बिंत जुबैल जिले को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, टायर जिले में गंधूरियेह और अब्बासियेह के बीच के इलाके में भी हवाई हमला किया गया। इसके अलावा इजराइली सेना की तोपों से सिद्दीकीन कस्बे पर बमबारी की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत में सहमति नहीं बनने के बीच इजरायल एक बार फिर ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की तैयारी में जुट गया है।

ईरान युद्ध को रोकना जरूरी : शी जिनपिंग

इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक, बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया फिर जंगलराज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने चेतावनी दी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकतरफा सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दुनिया को ऐसे दौर में ले जा सकता है, जहां अंतरराष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई रोकना बेहद जरूरी है। जिनपिंग ने यह बयान बुधवार को बीजिंग में पुतिन के औपचारिक स्वागत के बाद दिया।

झारखंड में पहली बार एक साथ 201 डीएसपी की ट्रांसफर-पोस्टिंग

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को हेमंत सरकार ने राज्य पुलिस सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। पहली बार एक साथ 201 डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कई जिलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, यातायात डीएसपी, विशेष शाखा और मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे राज्य में लंबे समय बाद हुआ सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, कई जिलों के एसडीपीओ को नई जगहों पर भेजा गया है। गढ़वा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे नीरज कुमार को हटिया का डीएसपी बनाया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची में पदस्थापित दीपक कुमार को बेड़ो का डीएसपी बनाया गया है। हजारीबाग में झारखंड सशस्त्र पुलिस-7 में तैनात मनीष चंद्र लाल को सिल्ली का डीएसपी बनाया गया है। इसी तरह बसिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे नाजीर अख्तर को धनबाद मुख्यालय-2 भेजा गया है। बरही के एसडीपीओ अजित कुमार विमल को बाघमारा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। विशेष शाखा में तैनात लिलेश्वर महतो को निरसा और प्रकाश चंद्र महतो को सिंदरी का एसडीपीओ बनाया गया है।

गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन

- कई जिलों के एसडीपीओ, यातायात डीएसपी, विशेष शाखा और मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
- गढ़वा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे नीरज कुमार बने हटिया के डीएसपी
- कुमार विनोद को धनबाद में मुख्यालय-4 का बनाया गया डीएसपी

रांची और धनबाद में बड़ा बदलाव

राजधानी रांची और धनबाद जिले में भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई है। कई परिवीक्षाधीन डीएसपी अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। आलोक कुमार सिंह को सीसीआर रांची, अजय आर्यन को डीएसपी मुख्यालय-2 रांची और रामाकांत रजक को यातायात-4 रांची में पदस्थापित किया गया है। ताराश सोरेन को यातायात-2 रांची की जिम्मेदारी मिली है। वहीं, प्रदीप कुमार-2 को साइबर डीएसपी रांची बनाया गया है। कुमार विनोद को धनबाद में मुख्यालय-4 का डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को ट्रैफिक, साइबर सेल और विशेष शाखा में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की इस कार्रवाई को आगामी कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जरूरतों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध पर निगरानी, ट्रैफिक प्रबंधन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर पुलिसिंग के उद्देश्य से यह व्यापक बदलाव किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि नई पोस्टिंग से पुलिस प्रशासन अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनेगा। जिन जिलों में लंबे समय से अधिकारी तैनात थे, वहां भी बदलाव किया गया है, ताकि कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा लाई जा सके।

रक्षा, व्यापार और तकनीक में आपसी सहयोग से और मजबूत होंगे रिश्ते

भारत-इटली संबंधों को मिली नई गति : पीएम

NEW DELHI @ PTI : बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली के संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने की घोषणा की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों में उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी से कई बार मिलने का अवसर मिला है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते करीबी सहयोग और बेहतर सामंजस्य को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व में भारत-इटली संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 दोनों देशों की साझेदारी को व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख ढांचा प्रदान करती है। इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है।

दोनों देशों ने की स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा

कनेक्टिविटी के क्षेत्र में स्वाभाविक सहयोग

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग दोनों देशों के गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। यह सहयोग केवल सेनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने सह-विकास और सह-उत्पादन की दिशा में नया मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि समुद्री शक्तियों के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग स्वाभाविक है। दोनों देश मिलकर शिपिंग, बंदरगाह आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकॉनमी के क्षेत्रों में काम करेंगे।

उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ 12 मित्र देशों के साथ सैन्य अभ्यास 'प्रगति'

NEW DELHI : मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बुधवार से बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 'प्रगति' शुरू हो गया। इस सैन्य अभ्यास में भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम सहित 12 मित्र देश भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने इन सैन्य टुकड़ियों का गर्मजोशी और पारंपरिक रूप से स्वागत करके भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य सत्कार को दशार्या। सैन्य अभ्यास 'प्रगति' (पीआरएजीएटीआई) का अर्थ हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी है, जो समानता, मित्रता और आपसी सम्मान की भावना से आयोजित की जा रही है।

बड़ी उपलब्धि हवा से सतह व हवा से हवा में मार करने की क्षमता का हुआ परीक्षण

अब मानव रहित हवाई वाहन से दागी जा सकेंगी मिसाइलें

NEW DELHI @ PTI : भारत अब मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) से सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 प्रक्षेपित कर दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हुए अंतिम विकास परीक्षण में यह उपलब्धि हासिल हुई है। डीआरडीओ ने हवा-से-सतह और हवा-से-हवा में मार करने की क्षमता वाले यूएवी से यह परीक्षण किए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में हवा-से-सतह और हवा-से-हवा में मार करने की क्षमता वाले मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 के अंतिम परिशोधित विन्यास के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण एकीकृत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम (जीसीएस) के माध्यम से संचालित किए गए। इसका उद्देश्य यूएलपीजीएम हथियार प्रणाली का प्रभावी कमांड एवं नियंत्रण सुनिश्चित करना था। यह जीसीएस प्रणाली अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जो तत्परता, लक्ष्य निर्धारण और प्रक्षेपण प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाकर मिशन की दक्षता और सटीकता को बढ़ाती है।

दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई लक्ष्यों को बनाया जा सकता है निशाना

कई संस्थानों का मिला महत्वपूर्ण सहयोग

डीआरडीओ ने मिसाइलों के विकास और उत्पादन के लिए हैदराबाद स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड और हैदराबाद स्थित अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नामक दो उत्पादन एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। वर्तमान परीक्षणों के लिए इस प्रणाली को बेंगलुरु स्थित न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित यूएवी में एकीकृत किया गया है। यूएलपीजीएम मिसाइल को हैदराबाद स्थित इमारत अनुसंधान केंद्र द्वारा नोडल प्रयोगशाला के रूप में अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं जैसे कि हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं डीआरडीएल, टीबीआरएल ,एचईएमआरएल के साथ मिलकर विकसित किया गया है।

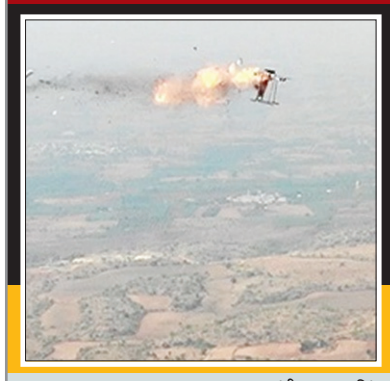

आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास डीआरडीओ परीक्षण रेंज में पूरी की गई प्रक्रिया

- परीक्षण एकीकृत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से किए गए संचालित
- अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है जीसीएस प्रणाली, तत्परता व लक्ष्य निर्धारण में सटीक

भारत डायनामिक्स लिमिटेड व अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ की गई है साझेदारी

पूरी टीम को रक्षा मंत्री ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत को यूएलपीजीएम-वी3 के सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा-से-सतह तथा ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई लक्ष्यों पर हमले के लिए हवा-से-हवा मोड में इसकी सफलता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने परीक्षणों से जुड़ी सभी टीमों को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी।

टेक्नीशियन की मदद से शव को उतारा गया नीचे

रांची में युवक ने हाईटेंशन टावर पर चढ़ लगाई फांसी, प्रेमिका से हुआ था विवाद

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के कादोजोरा गांव में एक हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़कर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के चेटो परसा गांव निवासी जट्टू उरांव के 18 वर्षीय पुत्र बिरसा उरांव के रूप में हुई है। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। सुबह ग्रामीणों ने टावर पर शव लटका देखा, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही बेड़ो थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल बिजली विभाग को सूचित कर बिजली कटवाई। इसके बाद टेक्नीशियन की मदद से शव को टावर से नीचे उतारा गया। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों के अनुसार, बिरसा उरांव का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक, आत्महत्या से एक दिन पहले बिरसा का अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आवेश में आकर उसने यह कदम उठाया।

हाईटेंशन टावर पर लटकता युवक का शव।

BRIEF NEWS

पलामू के 8 गुड समरिटान को मिला दो हजार का चेक

PALAMU : उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले 8 गुड सेमेरिटीन (नेक व्यक्तियों) को दो-दो हजार रुपये का चेक सौंपकर सम्मानित किया। मौके पर डीटीओ जितेंद्र यादव उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा मानवता का कार्य है। ऐसे लोगों को सम्मानित करना प्रशासन के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी सम्मानित व्यक्तियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी तत्परता और संवेदनशीलता के कारण कई लोगों की जान बच सकी। चेक प्राप्त करने वालों में गुलाम मुस्तफा, बसंत कुमार, अशोक कुमार यादव, संजीव कुमार चंद्रवंशी, जफर इमाम, विजय पांडे, पवन कुमार और आलोक पटेल शामिल थे। छतरपुर के कचनपुर निवासी अशोक कुमार यादव ने 13 अप्रैल को मदनपुर में घायल हुए व्यक्ति को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया था। वहीं मुरूमदाग निवासी गुलाम मुस्तफा ने 15 अप्रैल को सिलदाग में हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पुलिस केस समझकर नजरअंदाज न करें। गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने से किसी की जान बचायी जा सकती है। सरकार की ओर से गुड सेमेरिटीन योजना के तहत मदद करने वाले लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि आमजन आगे आएं, मानवता का परिचय दें और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं।

धनबाद पुलिस को मिलीं 45 हाईटेक बाइकें

DHANBAD : धनबाद पुलिस अब अपराधियों पर और तेजी से शिकंजा कसने की तैयारी में है। बुधवार को पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने 45 पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी थानों को कुल 45 अत्याधुनिक बाइक उपलब्ध कराई गई है, जो अपराध नियंत्रण और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। इन बाइकों में सायरन, ब्लिंकर्स और जीपीएस जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी थानों और सिटी हॉक्स को नई बाइक उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद अब धनबाद पुलिस के पास करीब 250 पेट्रोलिंग बाइक हो चुकी हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि इन बाइकों का उद्देश्य पुलिसिंग को मजबूत करना है, ताकि जहां चारपहिया वाहन नहीं पहुंच पाते वहां पुलिस तेजी से मौके पर पहुंच सके।

आजसू की बैठक में हुई फायरिंग छात्र नेता सहित कई समर्थक घायल

कोयला कारोबार से जुड़े लोगों को मिल रही थी धमकी, इसी मुद्दे पर होनी थी चर्चा

PHOTON NEWS DHANBAD : धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा में बुधवार को आजसू नेताओं की बैठक के दौरान फायरिंग हो गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि बैठक के बीच में कुछ लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हमले के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जबकि कई कार्यकताओं के साथ मारपीट की गई।

हमले में आजसू छात्र नेता हीरालाल महतो सहित कई समर्थक घायल हो गए। हीरालाल महतो ने आरोप लगाया कि रजनी रवानी को पिछले कुछ दिनों से कथित कोयला कारोबार से जुड़े लोगों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कार्यकर्ता बैठक में जुटे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमले के दौरान गोली भी चलाई गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग में घायल युवक की पहचान किशन रजवार के रूप में हुई है। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

मामले की जांच करने पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही लोयाबाद के थाना प्रभारी टीकू प्रसाद दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटना हुई है और एक व्यक्ति गोली का शिकार हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमले में शामिल लोगों की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

विशेष मुहिम में सैकड़ों वारंटों का किया निष्पादन

DHANBAD : जिला पुलिस ने न्यायालय से जारी लंबित वारंटों के निष्पादन को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थानों और ओपी क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई के दौरान मई के पहले 15 दिनों में अभियुक्त वारंट के 664 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा स्थायी वारंट के 85 मामलों में कार्रवाई पूरी की गई। कुर्की से जुड़े 9 मामलों का भी निष्पादन किया गया। इस प्रकार कुल 758 मामलों में कार्रवाई कर पुलिस ने लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एसएसपी ने बताया कि कई अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि लंबित वारंटों के निष्पादन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जून के अंत तक अधिकतम लंबित वारंटों का निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। अभियान की मॉनिटरिंग डीएसपी मुख्यालय-2 धीरेंद्र नारायण बंका कर रहे हैं। तकनीकी संसाधनों की मदद से फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान से न केवल पुराने मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी, बल्कि अपराधियों में कानून का भय भी बढ़ेगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते एसएसपी प्रभात कुमार व अन्य

स्कूल में 10वीं के छात्र से मारपीट, कार्रवाई की मांग

DHANBAD : धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करमाटांड़ स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल में 10 वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के ही 9 वीं कक्षा के पांच छात्रों ने 10 वीं के एक छात्र को स्कूल के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। घटना में घायल छात्र को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसएनएमएमएएच) में भर्ती कराया गया है। घायल छात्र की पहचान तरुण कुमार के रूप में हुई है। छात्र के पिता बलराम चौधरी ने बताया कि उनका बेटा बुधवार को स्कूल गया था। इसी दौरान कुछ छात्रों ने उसे पकड़कर स्कूल के बाथरूम में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने के बाद वे स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से आरोपित छात्रों की जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बलराम चौधरी ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय संबंधित छात्रों को घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से दोषी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घायल छात्र तरुण कुमार ने बताया कि वह बाथरूम में था तभी पांच छात्र वहां पहुंचकर उसे पकड़कर बिना किसी वजह बताए उसकी पिटाई करने लगे। मारपीट में उसके सिर और छाती में चोट आई है। मामले में स्कूल संचालक ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है और जांच के बाद दोषी छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने इलाज के बाद बलियापुर थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करने की बात कही है।

नई क्लस्टर सिस्टम नीति के खिलाफ धनबाद में आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन

AGENCY DHANBAD : झारखंड सरकार द्वारा लागू की जा रही नई क्लस्टर सिस्टम नीति के विरोध में बुधवार को आजसू छात्र संघ ने धनबाद में प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित विरोध कार्यक्रम में छात्र नेताओं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने किया। इस दौरान बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी सहित जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार की कथित छात्र-विरोधी नीति के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार से क्लस्टर सिस्टम नीति वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रा श्रेया रॉय ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को छिपाने के लिए क्लस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कॉलेजों में वर्षों से प्रोफेसरों के हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन स्थायी नियुक्ति करने के बजाय सरकार एक कॉलेज के शिक्षक को दूसरे कॉलेज में भेजकर शिक्षा व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। कई कॉलेजों में आर्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्रों को एक विषय की पढ़ाई अपने कॉलेज में और दूसरे विषय की कक्षाएं किसी दूसरे कॉलेज में करनी पड़ सकती हैं। इससे खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। छात्रों को रोजाना अलग-अलग कॉलेजों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और पैसे दोनों की बबार्दी होगी। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बिना बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किए केवल कागजी योजनाओं को लागू करने में लगी हुई है। उनका कहना था कि सरकारी कॉलेजों में पहले से ही क्लासरूम, बेंच-डेस्क, पुस्तकालय और शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को एक ही जगह समायोजित करना व्यवहारिक नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालयों में पहले से लेट चल रहे शैक्षणिक सत्र पर भी चिंता व्यक्त की।

सीएम का पुतला दहन करते आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ता

गिरिडीह में दो दिन से लापता छात्रा का पुल के नीचे मिला शव, सनसनी

PHOTON NEWS GIRIDIH : गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो दिनों से लापता 11वीं की छात्रा का बुधवार को शव मिला, तो इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा का शव बरगंडा में पुराने पुल के पास उसरी नदी के नीचे मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका का नाम पायल कुमारी है। वह सिरसिया स्थित वार्ड नंबर-12 की रहने वाली थी। पायल पढ़ाई के साथ-साथ सिलाई सीखती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। परिजनों ने बताया कि पायल सोमवार को सुबह घर से ट्यूशन और सिलाई प्रशिक्षण के लिए निकली थी। वह रोज दोपहर तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन तय समय तक नहीं लौटी। जब घरवालों ने फोन किया तो उसने बताया कि वह ब्लॉक से निकल रही है और जल्दी घर पहुंच जाएगी। इसके कुछ देर बाद जब दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद परिवार ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल डिटेल और उसके परिचितों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को सुबह में छात्रा का शव मिलने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

घटनास्थल पर जुटी भीड़

नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मौसा गिरफ्तार

LOHARDAGA : लोहरदगा : लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस बच्ची के मौसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेडिकल परीक्षण के बाद बच्ची को फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में रखा गया है। जानकारी के अनुसार, बच्ची मूल रूप से लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पिता के दूसरे विवाह और मां के रोजगार के सिलसिले में चेन्नई में रहने के कारण बच्ची अपनी मौसी के घर कैरो थाना क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। आरोप है कि इसी दौरान मौसा बच्ची को घर में अकेला पाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसके साथ ही किसी को घटना की जानकारी नहीं देने की धमकी देता था। बताया जा रहा है कि बुधवार को आरोपी मौसा ने फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद आरोपी इलाज के लिए बच्ची को लेकर कुडू स्थित अस्पताल पहुंचा। वहां बच्ची को छोड़कर वह भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मामले की सूचना पुलिस को मिल गई। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और कुडू बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में पीड़िता की मौसी ने अपने पति के खिलाफ कैरो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। कैरो के थाना प्रभारी कुंदन कुमार रवानी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

देवघर में ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर किए गए गिरफ्तार

AGENCY DEOGHAR : देवघर पुलिस ने नशा और ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दहीजोर-लेटवावरण सड़क स्थित तिराहा मोड़ के पास ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान गौतम महथा उर्फ गौतम चौधरी को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपित ने ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले मुख्य सरगना फिरोज अंसारी उर्फ गुड्डू का नाम बताया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हंसडीहा थाना क्षेत्र निवासी फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे संगठित तरीके से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री का अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित गौतम महथा के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में मोहनपुर थाना कांड संख्या 77/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर) अशोक कुमार सिंह ने किया।

गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

चर्चा

ग्रामसभा में मुखिया व प्रधान ने मांगी माफी, शव की पहचान कराने में जुटी पुलिस

जिसे मृत समझकर दफनाया, वह लौट आया जिंदा

PHOTON NEWS KHUNTI : खूंटी जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति जिंदा घर लौट आया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों के बीच चर्चा का माहौल बन गया। मामला मारंगहादा थाना क्षेत्र के पतराटोली गांव का है। यहां ग्रामीणों और परिजनों ने एक अज्ञात शव को गांव के निवासी विश्राम मुंडा समझकर सामाजिक रीति-रिवाज के साथ दफना दिया था। बाद में जब विश्राम मुंडा खुद घर लौटे तो परिवार और गांव के लोग हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार, 11 मई को खूंटी थाना क्षेत्र के डडगामा गांव के पास की नाली से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी थी। इसी दौरान विश्राम मुंडा के परिजन और ग्रामीण पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान विश्राम मुंडा के रूप में कर दी। पहचान के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद गांव में पूरे सामाजिक रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर शव को दफना दिया गया।

गांव में घटना के बारे में बताते ग्रामीण

जिंदा लौटते ही गांव में मची सनसनी

घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद विश्राम मुंडा अचानक जिंदा घर लौट आया। वह सीधे खूंटी में अपनी बेटी के किराए के मकान पहुंचा। उसे सामने देखकर परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल बन गया और पंचायत स्तर पर बैठक बुलाई गई।

अब होगी अज्ञात शव की दोबारा पहचान

इस मामले पर एसडीपीओ वरुण रजक ने कहा कि जिस शव को विश्राम मुंडा समझकर दफनाया गया था, उसकी दोबारा पहचान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम आवश्यक साक्ष्य जुटा चुकी है। यदि कोई व्यक्ति शव की पहचान के लिए सामने आता है तो डीएनए जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, कानून के तहत 72 घंटे तक पहचान नहीं होने पर अज्ञात शव का अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होता है।

पंचायत ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

मामले की जानकारी मिलने के बाद ग्राम सभा सक्रिय हुई। पंचायत के मुखिया प्रेम तुती ने बताया कि शव की पहचान फोटो के आधार पर की गई थी। चेहरा काफी मिलता-जुलता होने के कारण ग्रामीण और परिजन भ्रमित हो गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा कि यह भूल अनजाने में हुई है। ग्राम प्रधान जोलेन तूती ने भी माना कि जल्दबाजी में शव की पहचान कर ली गई थी।

शादी समारोह से लापता हुआ था विश्राम मुंडा

बताया गया कि विश्राम मुंडा 10 मई को अपने परिवार के साथ डडगामा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गया था। वहीं से वह अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। इसी दौरान नाली से मिले शव की तस्वीर सामने आई। ग्रामीणों और परिवार वालों ने तस्वीर देखकर उसे विश्राम मुंडा समझ लिया। बताया गया कि मृतक का चेहरा काफी हद तक विश्राम मुंडा से मिलता-जुलता था, जिसके कारण यह भ्रम पैदा हो गया।

● एसडीपीओ वरुण रजक ने कहा- अब डीएनए जांच के आधार पर की जाएगी पहचान

घूमने चला गया था रामगढ़

जीवित लौटे विश्राम मुंडा ने बताया कि वह बिना किसी को जानकारी दिए रामगढ़ घूमने चला गया था। उसने परिवार को अपने जाने की सूचना नहीं दी थी, जिसके कारण सभी लोग परेशान हो गए। विश्राम मुंडा ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया और कहा कि उसकी वजह से गांव और परिवार को परेशानी उठानी पड़ी।

अफीम की जगह हरी सब्जियों की खेती पर दिया गया जोर

कार्यशाला में किसानों को जानकारी देते विशेषज्ञ

KHUNTI : जिले में आगामी खरीफ मौसम और कम वर्षा की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला-सह-किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर संयुक्त कृषि भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में वैज्ञानिक खेती, वैकल्पिक फसल और आधुनिक कृषि तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऐसी फसलों के प्रति जागरूक करना था, जिन्हें कम वर्षा की स्थिति में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सके। कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने किसानों को आकस्मिक फसल योजना, वैकल्पिक खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि बदलते मौसम और अनियमित वर्षा को देखते हुए खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है। पशुपालन विभाग ने चारा की उपलब्धता, पशुओं के टीकाकरण और पशुधन संरक्षण की जानकारी साझा की।

जमीन की अड़चन से धीमी हुई वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे की गति

वन भूमि क्लीयरेंस के कारण अब तक एक ही सेक्शन में शुरू हो पाया काम

PHOTON NEWS RANCHI : भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे वाराणसी- कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का काम झारखंड में जमीन अधिग्रहण और वन भूमि क्लियरेंस की वजह से धीमी गति से चल रहा है। राज्य में बनने वाले 202 किलोमीटर हिस्से के लिए कुल छह पैकेज तय किए गए हैं, लेकिन अब तक केवल एक पैकेज में ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। शेष पांच सेक्शन में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण काम अटका हुआ है। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के चंदौली से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक बनाया जाना है। झारखंड में यह सड़क चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और बोकारो जिले से होकर गुजरेगी। राज्य में पैकेज संख्या आठ से 13 तक निर्माण होना है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) सूत्रों के अनुसार पैकेज-8 चतरा, पैकेज-9 हजारीबाग, पैकेज-10 रामगढ़, पैकेज-11 रांची तथा पैकेज-12 और 13 बोकारो जिले में प्रस्तावित हैं। इनमें से सिर्फ बोकारो के अंतिम सेक्शन में निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। यहां मिट्टी भराई और सड़क बेस तैयार करने का काम चल रहा है, जबकि बाकी पांच सेक्शन भूमि विवाद और अधिग्रहण प्रक्रिया में फंसे हैं।

» प्रदेश में बनने वाले 202 किलोमीटर हिस्से के लिए तय किए गए हैं छह पैकेज

» चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और बोकारो जिले से होकर गुजरेगी यह सड़क

प्रतीकात्मक फोटो

हजारीबाग और रामगढ़ में वन भूमि सबसे बड़ी बाधा

हजारीबाग और रामगढ़ सेक्शन में वन भूमि सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कई हिस्सों में जंगल क्षेत्र पड़ने के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं चतरा और रांची क्षेत्र में रैयती जमीन अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया धीमी बतायी जा रही है।

2023 में ही फाइनल हो गए थे टेंडर

जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना के लिए टेंडर वर्ष 2023 में ही फाइनल कर दिए गए थे और एजेंसियों को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। बावजूद इसके, तीन साल बाद भी जमीन उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश हिस्सों में मशीनें नहीं उतर सकी हैं। एनएचएआई चेयरमैन स्तर से भी राज्य सरकार और संबंधित जिलों को कई बार पत्र भेजे गए हैं।

वर्ष 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य

अधिकारियों का कहना है कि जमीन मिलते ही बाकी सेक्शनों में भी तेजी से निर्माण शुरू कराया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद झारखंड के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। माल ढुलाई तेज होगी और रांची, रामगढ़ व बोकारो जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सीधे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मजबूत होगी। एनएचएआई ने इस एक्सप्रेस-वे को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन फिलहाल लंबित पांच सेक्शन के कारण परियोजना की रफ्तार पर बड़ा असर पड़ रहा है।

BRIEF NEWS

महिला से मोबाइल लूट मामले का खुलासा, तीन धराए

RANCHI : हरमू स्थित पटेल चौक के पास महिला से चाकू मारकर मोबाइल लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो अपराधियों और एक विधि विरुद्ध किशोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल की दोपहर हरमू के पटेल चौक के पास बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने एक महिला पर चाकू से हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना में महिला घायल हो गई थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरमू क्षेत्र से दो अपराधियों और एक किशोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में मो अली उर्फ सुफियान अली और अब्बू रेहान उर्फ आर्यन शामिल हैं। दोनों की उम्र करीब 19 वर्ष बताई गई है और दोनों हिंदीपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर नदी ग्राउंड के रहने वाले हैं।

रांची टेंडर घोटाले में आरोपी इंजीनियर ने किया आत्मसमर्पण

RANCHI : ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आए अधिशाषी अभियंता सिद्धांत कुमार ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी।

कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिना न्यायालय की अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाने और जांच एजेंसियों को सहयोग करने की शर्त भी लगाई गई है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं।

फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी सोनू यादव पटना से अरेस्ट

RANCHI : राजधानी के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित तेल मील गली में हुए चर्चित फायरिंग मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सोनू यादव को पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में रांची लाया गया। उससे लगातार पूछताछ जारी है। मामले में अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार पंडरा इलाके में 19 जनवरी को 55 लाख रुपये के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान आकाश सिंह और विकास सिंह पर गोलीबारी की गई थी।

मंत्री ने की ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा

सड़क निर्माण कार्य लटकाने वाले संवेदक होंगे डिबार : दीपिका पांडेय

रेट रिवीजन का लाभ लेने के लिए जानबूझकर योजनाओं को रखते हैं लंबित

जिलावार सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं की स्थिति से हुई अवगत

PHOTON NEWS RANCHI : ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने लंबे समय से अधूरी सड़क निर्माण योजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा के भीतर सड़क और पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों और संवेदकों की सूची तैयार कर उन्हें डिबार करने की प्रक्रिया तेज करें। रांची स्थित झारखंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने जिलावार सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सामने आया कि कई जिलों में वर्षों से सड़क निर्माण कार्य लंबित है, जबकि संबंधित एजेंसियां दूसरी नई योजनाएं भी ले रही हैं।

इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने वालों को अब नया काम मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कई मामलों में रेट रिवीजन का लाभ लेने के लिए जानबूझकर योजनाओं को लंबित रखा जाता है। विभाग अब ऐसी योजनाओं की भी जांच करेगा, जिनमें लागत संशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

बैठक में भाग लेतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह व अन्य • फोटोन न्यूज

क्षतिग्रस्त पुलों की बनाएं सूची

उन्होंने बारिश से पहले राज्य के क्षतिग्रस्त पुलों की सूची तैयार कर उनकी मरम्मत और निरीक्षण का कार्य तेज करने का निर्देश भी दिया। साथ ही अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण करने को कहा। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। राज्य के छह जिलों में पलाश मार्ट निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए नई कार्य योजना तैयार की जाए।

विधायकों की अनुशंसा पर शीघ्र हो कार्रवाई

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। समीक्षा बैठक में विधायकों द्वारा भेजी गई शिकायतों और मांगों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण में अनियमितता या नई सड़क की मांग से जुड़े मामलों में सिर्फ पत्राचार कर औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि समयबद्ध जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अबुआ आवास योजना में लाएं तेजी

अबुआ आवास योजना की समीक्षा के दौरान लाभुकों को अंतिम किस्त का भुगतान कर जल्द आवास निर्माण पूरा कराने पर जोर दिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या करीब 3 लाख 19 हजार तक पहुंच चुकी है। बैठक में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने कहा कि डेढ़ साल तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले संवेदकों की सूची जिला स्तर से मुख्यालय भेजी जाए। साथ ही रेट रिवीजन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी, ताकि काम में देरी कर लाभ लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। बैठक में मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

NEWS BOX

एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू स्कूटी से निकले दो केंद्रीय मंत्री

PHOTON NEWS RANCHI : रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की शुरूआत की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 'उड़ान यात्री कैफे' समेत कई आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस कैफे में यात्रियों को ₹10 में चाय और ₹20 में स्नैक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। के राम मोहन नायडू ने दोहराया कि रांची एयरपोर्ट को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा और डाल्टनगंज जैसे शहरों को भी जोड़ा जाएगा। रांची आगमन पर भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी से शहर का भ्रमण कर ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

बीएसआईडीसी की संपत्तियों और कर्मियों के बकाए पर हाईकोर्ट सख्त

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) से जुड़े कर्मचारियों के लंबित दावों और झारखंड में स्थित परिसंपत्तियों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निगम से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने बीएसआईडीसी को निर्देश दिया है कि वह शपथपत्र दाखिल कर निगम की वर्तमान स्थिति, कर्मचारियों के बकाया दावों और झारखंड में मौजूद परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराए। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बीएसआईडीसी को निर्देश दिया कि वह शपथपत्र दाखिल कर निगम की वर्तमान स्थिति, कर्मचारियों के लंबित दावों तथा झारखंड में स्थित परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए। वहीं, कर्मचारियों और हस्तक्षेपकताओं को भी यह बताने के लिए विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है कि अब तक उन्हें कितना भुगतान किया गया है और उनकी शेष मांगें क्या हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को 30 जून तक शपथपत्र दाखिल कर उसका आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सभी पक्षों को 24 जुलाई 2026 तक संक्षिप्त लिखित बहस दाखिल करनी होगी। गौरतलब है कि बीएसआईडीसी के झारखंड में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान को लेकर जनहित याचिका दायर की है।

जमीन मुआवजा मामले में सीसीएल को झटका, सभी अपीलें खारिज

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट, 1957 के तहत अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़े चार प्रथम अपील मामलों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की सभी अपीलें खारिज कर दी हैं। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे को उचित ठहराते हुए उसके आदेश को बरकरार रखा। मामला हजारीबाग जिले के मांडू थाना क्षेत्र स्थित पिंडरा गांव की जमीन अधिग्रहण से जुड़ा था। सीसीएल ने वर्ष 1981 में कोयला खनन परियोजना के लिए खाता संख्या 4 और 6 की भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके बाद जमीन मालिकों ने मुआवजा कम मिलने का आरोप लगाते हुए अधिक मुआवजे की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने 30 मई 2013 को दिए गए अपने फैसले में अधिग्रहित जमीन का बाजार मूल्य 600 रुपये प्रति डिसमिल निर्धारित किया था। ट्रिब्यूनल ने इसके अलावा 30 प्रतिशत सोलाटियम, 12 प्रतिशत वार्षिक एस्केलेशन तथा बढ़ी हुई राशि पर 9 प्रतिशत और बाद के वर्षों में 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया था। सीसीएल ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा था कि ट्रिब्यूनल ने मुआवजा अत्यधिक बढ़ा दिया है और विकास लागत (डेवलपमेंट कॉस्ट) की कटौती नहीं की गई।

लखनऊ घटना के विरोध में रांची के अधिवक्ता आज करेंगे प्रदर्शन

PHOTON NEWS RANCHI : लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना एवं अधिवक्ताओं के चेंबर तोड़े जाने के विरोध में रांची जिला बार एसोसिएशन (फ्ब्इअ) के बैनर तले अधिवक्ता गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध कार्यक्रम रांची सिविल कोर्ट परिसर में न्यायालय कार्य अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा। रांची जिला बार एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अधिवक्ता समाज में आक्रोश है। इसके विरोध में रांची के अधिवक्ता एकजुटता प्रदर्शित करते हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे 21 मई को न्यायालय परिसर में काला बिल्ला लगाकर अपने कार्य का निष्पादन करें तथा लखनऊ के अधिवक्ताओं के समर्थन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बार एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि घटना में शामिल दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बच्चों का उपयोग पोर्नोग्राफी में नहीं किया जा सकता : डालसा

PHOTON NEWS RANCHI : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से बुधवार को नालसा योजना जागृति 2025 के तहत सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कांके में लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया गया। साथ ही आदिवासी चौक और आईटीआई बस स्टैंड क्षेत्र में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन न्यायमूर्ति सह कार्यपालक अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश, सदस्य सचिव झालसा कुमारी रंजना अस्थाना और न्यायायुक्त रांची अनिल कुमार के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव राकेश रौशन की मौजूदगी में किया गया।

बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा नेता एवं बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका एसटी/एससी के विशेष न्यायालय में खारिज हो गई। सुनवाई के दौरान स्वयं याचिकाकर्ता की ओर से अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। मामला अरगोड़ा थाना में दर्ज बाल श्रम से जुड़े केस से संबंधित है। इस मामले में अदालत ने सुनील तिवारी के खिलाफ समन जारी किया था।

नई तकनीकों को सीखने वाले युवा ही भविष्य का नेतृत्व करेंगे : राज्यपाल

PHOTON NEWS RANCHI : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आने वाला समय उन्हीं युवाओं का होगा, जो नई तकनीकों को सीखने, अपनाने और नवाचार करने की क्षमता रखते हों। उन्होंने कहा कि स्वचालन (ऑटोमेशन), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स और स्मार्ट प्रणालियों जैसी आधुनिक तकनीकें उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही हैं। इसलिए युवाओं को उद्योगोन्मुख तकनीकी कौशल से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

राज्यपाल बुधवार को सिल्ली पॉलीटेक्निक में आयोजित उद्योगोन्मुख स्वचालन एवं आईओटी प्रणालियों पर राष्ट्रीय प्रायोगिक कार्यशाला (आईएओटी-26) के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा तभी सार्थक होती है, जब विद्यार्थियों को प्रयोग, नवाचार और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने का अवसर मिले। उन्होंने हाल ही में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पास एआई और नई तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड युवा शक्ति से परिपूर्ण राज्य है और यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।

- केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित न रहें, ज्ञान और कौशल को करें अपडेट
- भारत के पास एआई और नई तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की है क्षमता

सीएसआर फंड प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर हो खर्च : संजय यादव

RANCHI : उद्योग मंत्री झारखंड संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग फैक्ट्री और माइन्स से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विकास कार्यों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित लोगों को सीएसआर योजनाओं का सीधा लाभ मिलना जरूरी है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और लोगों का कंपनियों पर भरोसा बढ़े। वे बुधवार को रांची में आयोजित सीएसआर कॉनक्लेव 2026 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक घरानों, कंपनियों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कॉर्पोरेट जगत मिलकर रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुटीर उद्योग और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

विकेंद्रित उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलती है मजबूती : कल्पना सोरेन

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के गांडेय विधानसभा क्षेत्र की विधायक कल्पना सोरेन ने महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को रेखांकित करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विचारोत्तेजक संदेश साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने 'संघे शक्ति कलियुगे' की अवधारणा का उल्लेख करते हुए प्रसिद्ध सहकारी संस्था 'श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़' को महिला सशक्तीकरण का जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण बताया। कल्पना सोरेन ने विशेष रूप से 'डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोडक्शन' यानी विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली की सराहना की। कहा कि यह मॉडल महिलाओं को अपने घर या स्थानीय स्तर पर रहकर काम करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन पाती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार के लिए घर छोड़कर दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

- लिज्जत पापड़ मॉडल को बताया महिला सशक्तीकरण का प्रेरक उदाहरण

योजना

जिन कर्मियों की पूर्व सेवा नई में जोड़ी जाएगी, उनकी कटौती पुराने खाते में रहेगी जारी

जीपीएफ नंबर आवंटन के लिए नई एसओपी हुई लागू

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखा संख्या आवंटित करने को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी इस व्यवस्था में पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना चुनने वाले कर्मियों को एन-सीरीज (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या लिंक्ड) जीपीएफ नंबर आवंटित किया गया है। ऐसे कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में जमा सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि सरकार को वापस करनी होगी।

- ओपीएस-एनपीएस कर्मियों के लिए अलग नियम
- पुरानी पेंशन योजना चुनने वाले कर्मियों को एन-सीरीज नंबर आवंटित

वहीं 31 अगस्त 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को स्वतः पुरानी पेंशन योजना के दायरे में रखते हुए डी-सीरीज जीपीएफ नंबर जारी किया जा रहा है। नई मानक संचालन प्रक्रिया में उन कर्मचारियों के लिए भी विस्तृत व्यवस्था की गई है, जो पहले किसी अन्य सेवा में कार्यरत थे और बाद में दूसरी सेवा में नियुक्त हुए हैं। निर्देश के अनुसार, जिन कर्मियों की पूर्व सेवा नई सेवा में जोड़ी जाएगी, उनकी जीपीएफ कटौती पुराने खाते में जारी रहेगी।

बाद में नई सेवा के अनुरूप नया जीपीएफ नंबर जारी कर पुरानी राशि उसमें स्थानांतरित की जाएगी और पुराना खाता बंद कर दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की पुरानी सेवा जोड़ने की पात्रता नहीं होगी, तो उसे पहले पुराने जीपीएफ या स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की राशि निकालनी होगी। इसके बाद घोषणा पत्र जमा करने पर नई सेवा के लिए डी-सीरीज जीपीएफ नंबर आवंटित किया जाएगा। केंद्र सरकार अथवा अन्य सेवाओं से झारखंड सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए भी अलग प्रक्रिया तय की गई है। सेवा जोड़ने की स्थिति और राशि वसूली की आवश्यकता के आधार पर एन-सीरीज या डी-सीरीज जीपीएफ नंबर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा में प्रोन्नत अधिकारियों के लिए भी नई प्रक्रिया लागू की गई है। ऐसे मामलों में पुरानी जीपीएफ राशि को नई सेवा के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। वित्त विभाग ने कहा है कि यदि किसी कर्मी की सेवा निरंतरता मान्य नहीं पाई जाती है, तो उसे नई व्यवस्था के तहत डी-सीरीज जीपीएफ नंबर आवंटित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री की मंजूरी मिल चुकी है।

संघ की सचिवालय सेवा संवर्ग समीक्षा समिति की कार्यप्रणाली पर आपत्ति

RANCHI : झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सचिवालय सेवा संवर्ग समीक्षा समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को आयोजित समिति की दूसरी बैठक के बाद संघ की ओर से कहा गया कि समिति की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित नहीं हो रही है। बैठक की अध्यक्षता राजस्व पर्षद के सदस्य मस्तराम मीणा कर रहे थे। इस बैठक में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और संघ की ओर से अध्यक्ष और महासचिव भी शामिल थे। संघ ने बताया कि बैठक के दौरान कार्मिक सचिव की ओर से विभिन्न राज्यों में सचिवालय सेवाओं के पदों की स्थिति का विवरण प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया।

जुगसलाई में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले छह बदमाश हुए गिरफ्तार

कपड़े के शोरूम पर हुई घटना का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड फरार

PHOTON NEWS JSR: जुगसलाई बाजार स्थित यूनिक कलेक्शन कपड़ा दुकान में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर एक आपराधिक गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई वैगन-आर कार भी बरामद की है।

सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि 15 मई को जुगसलाई बाजार में यूनिक कलेक्शन नामक कपड़ा दुकान पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए मेरून रंग की वैगन-आर कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पांच लोग सवार थे। तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर 19 मई को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ आर्यन, राहुल सिंह उर्फ बड़कू, राहुल सिंह उर्फ गेटलु, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, बानेश्वर नामता उर्फ मानस और अंकित खटीक उर्फ अंकित सोनकर को गिरफ्तार किया।

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते सिटी एसपी ललित मीणा ● फोटोन न्यूज

पुलिस ने इनके कब्जे से चार अवैध देशी पिस्तौल, पांच गोलियां, तीन खाली मैगजीन, एक खोखा, छह एंड्रॉयड मोबाइल फोन और मेरून रंग की वैगन-आर कार जब्त की। सिटी एसपी के अनुसार, गिरफ्तार छह आरोपियों में से चार का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग रंगदारी और धमकी देकर पैसे वसूलने का काम करते थे। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इस गिरोह के कई सदस्य पहले से जेल में बंद हैं।

एसपी ने बताया कि फायरिंग की घटना को पांच लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड और सहयोग करने वाले अन्य कई लोगों की भूमिका भी सामने आई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस इस मामले को संगठित अपराध और रंगदारी गिरोह से जोड़कर जांच आगे बढ़ा रही है।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

देसी पिस्टल व गोली के साथ युवक गिरफ्तार

JAMSHEDPUR : मानगो के लक्ष्मण नगर छठ घाट के पास मंगलवार को उलीडीह थाना की पुलिस ने एक युवक को दबोचा। सिटी एसपी ललित मीणा ने जानकारी दी कि तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल और तीन गोली बरामद किए। गिरफ्तार युवक की पहचान विश्वजीत सिंह उर्फ रॉकी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2025 में एमजीएम थाना में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इस अवैध हथियार के जरिए इलाके में रंगदारी वसूलने और अपना दबदबा कायम करने की योजना बना रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। सिटी एसपी ललित मीणा ने कहा कि जिले में अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सोनुवा में ट्रैक्टर से गिरा मजदूर, ट्रॉली से दबकर हो गई मौत

CHAIBASA : चक्रधरपुर-मनोहरपुर रोड (एनएच 320डी) पर सोनुवा थाना क्षेत्र के गोलमुंडा कुनुसाई के पास बुधवार को सुबह में एक सड?क हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक बिजली विभाग में ठेका मजदूर था। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है। सोनुवा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा पुराने खंभे व बिजली तार बदलने का काम चल रहा था। तार हटाकर केबल बिछाने का काम उत्तर प्रदेश के एक ठेकेदार को मिला है। इसी कार्य के लिए बुधवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली का सामान लेकर एनएच 320डी से कुनुसाई की ओर जा रही थी। ट्रैक्टर में ड्राइवर के साथ मजदूर भी बैठा था। कुनुसाई के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से मजदूर ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और पीछे लगी ट्रॉली की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत सोनुवा थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश से आया था। पुलिस ठेकेदार से संपर्क कर मृतक के परिजनों का पता लगा रही है।

समाचार सार

प्रोजेक्ट स्कूल पटमदा के समर कैंप में दिखा हुनर

JAMSHEDPUR : राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 19 से 21 मई तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं ने भी हुनर दिखाया। पहले दिन- खेल के साथ फिटनेस एवं सृजन के संग बचपन- विषय पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्कूलों में योगाभ्यास, फिटनेस एक्सरसाइज, दौड़, रस्सीकूद, पारंपरिक खेल और समूह आधारित मनोरंजक गतिविधियां कराई गईं। विद्यालय की शिक्षक अल्का कुमारी तथा कुमारी पूनम सिंह, अजीत सिंह सरदार ,माणिकचंद्र सहित प्रधानाध्यापिका डॉ. प्रियंका झा ने ज्वॉयफुल लर्निंग के तहत बच्चों को जुम्बा डांस के साथ विभिन्न व्यंजन तैयार करना भी सिखाया।

खरकई में मिला नवजात का शव

JAMSHEDPUR : आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र में खरकई नदी में एक नवजात का शव मिला है। बागबेड़ा के लोग जब बुधवार को बड़ौदा घाट की तरफ खरकई नदी के पास पहुंचे तो वहां देखा गया कि वहां एक नवजात का शव पड़ा है। इसकी सूचना बागबेड़ा थाना को दी गई। बागबेड़ा की पुलिस पहुंची तो पता चला कि मामला आदित्यपुर का है। इसके बाद आरआईटी थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद आरआईटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। पता लगाया जा रहा है कि नदी में शव किसने फेंका।

माझी पारगाना ने 100 विद्यार्थियों का किया सम्मान

GHATSILA : माझी पारगाना माहाल, धाड़ दिशोम ने बुधवार को पावड़ा स्थित अपने भवन में समारोह किया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के 26 प्री-मैट्रिक कोचिंग सेंटरों के श्रेष्ठ 100 छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में इन कोचिंग सेंटरों से कुल 874 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें से 589 प्रथम श्रेणी, 260 द्वितीय श्रेणी तथा 4 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तीन वर्षों से माझी पारगाना माहाल धाड़ दिशोम सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्री-मैट्रिक कोचिंग की व्यवस्था कर रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिरेन जेवियर टोपनो (ट्राइबल आईडेंटिटी हेड, टाटा स्टील), कार्यक्रम के अध्यक्ष बैजु मुर्मू, दीपक मुर्मू, सुनील मुर्मू आदि भी उपस्थित थे।

इलेक्ट्रिक वाहनों से उठेगा कूड़ा, सरयू ने किया उद्घाटन

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय की विधायक निधि से बुधवार को बैटरी से चलने वाले छह डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों का उद्घाटन किया गया। जेएनएसी कार्यालय परिसर में वाहनों का उद्घाटन करते हुए सरयू राय ने कहा कि कुछ वर्ष पहले वह कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) गए थे। वहां उन्होंने देखा कि बैटरी से चलने वाले वाहनों से कूड़ा उठाया जा रहा है। यह प्रयोग उन्हें बेहतर लगा। उन्होंने जमशेदपुर आकर इस संबंध में जेएनएसी में बात की। लगभग साल भर के बाद बैटरी वाले वाहनों का आज उद्घाटन हुआ। अब संकरी गलियों में भी ये वाहन आसानी से पहुंच जाएंगे और कूड़ा उठाएंगे। इससे साफ-सफाई का काम बढ़िया होगा। इन छह वाहनों की खरीद में 14 लाख 70 हजार रुपये खर्च हुए। सरयू राय ने कहा कि ऐसे बैटरी चालित वाहनों की आज बेहद जरूरत है। खास कर तब, जब प्रधानमंत्री पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जेएनएसी की ही तरह अन्य नगरपालिकाओं में भी बैटरी चालित वाहनों से कूड़ा उठाने का काम शुरू होगा। यह हर तरीके से मुफीद है। इसमें न पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा, न ही डीजल की। इस मौके पर जेएनएसी के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार भी मौजूद थे।

चाईबासा में बस की टक्कर से घायल बाइक चालक की मौत

PHOTON NEWS CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टाटा से चाईबासा आ रही मां पार्वती बस की मंगलवार को चलियामा में कुजू के पास एक बाइक से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को सदर अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस तेज रफ्तार से आ रही थी, जबकि बाइक विपरीत दिशा से चलियामा की तरफ जा रही थी। कुजू के पास मोड़ पर दोनों वाहनों की आमने-सामने सीधे टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के साथ-साथ बस का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गए। बाइक चालक सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस बस को जब्त कर थाने ले गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। वह सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर स्थित रोलाडीह गांव का रहने वाला था। सूरज डंपर चालक था। वह अपनी पत्नी को लाने चलियामा जा रहा था। इसी बीच बस से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया। दोपहर में इलाज के दौरान उसका निधन हो गया।

घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त बाइक व इनसेट में सूरज की फाइल फोटो

टाटा स्टील कलर इम्प्लाई यूनियन की नई टीम को मिली मान्यता

JAMSHEDPUR : टाटा स्टील कलर इम्प्लाई यूनियन को टाटा ब्लूस्कोप स्टील (अब टाटा स्टील कलर्स) कंपनी प्रबंधन ने बुधवार को मान्यता प्रदान की। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, कार्यकारी अध्यक्ष बिजय खां, महासचिव संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हुसैन ओला कादरी व पवन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव आदित्य राज, सहायक सचिव प्रवीण कुमार राय तथा यूनियन के पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, संतोष साहू, देव कुमार मिड्या एवं कृष्ण कुमार यादव उपस्थित थे। वहीं प्रबंधन की ओर से सीएचआरओ नीना बहादुर, प्लांट हेड इंद्रनील बिस्वास, डीजीएम एचआर-आईआर राजेश त्रिपाठी, डीजीएम फाइनेंस पीयूष कुमार, प्रोक्योरमेंट हेड दुतीमान हाजरा, फाइनेंस हेड विनीता अग्रवाल एवं एचआर मैनेजर ऋचा पांडेय मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान प्रबंधन एवं यूनियन प्रतिनिधियों ने बेहतर औद्योगिक संबंध, कर्मचारियों के हित एवं कंपनी की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की साथ ही लंबित वेज रिवीजन को भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रबंधन से अनुरोध किया, ताकि कर्मचारियों को वेज रिवीजन का लाभ शीघ्र मिल सके।

गुवा के तीन बच्चे छह दिनों से लापता, दहशत में परिजन

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र से तीन बच्चे छह दिनों से लापता हैं। 15 मई को घर से खेलने निकला ठाकुरा गांव निवासी 13 वर्षीय दर्शना चाम्पिया अपने दो दोस्तों के साथ अब तक वापस नहीं लौटा है। तीनों बच्चों का कोई सुराग न मिलने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में चिंता व भय का माहौल है। दर्शना के पिता सुकरा चाम्पिया ने बताया कि 15 मई की दोपहर उनका बेटा गुवासाई स्कूल से पढ़कर घर आया था। खाना खाने के बाद वह गांव के ही दो दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवार ने खोजबीन शुरू की। गांव, आसपास के टोले, रिश्तेदारों और परिचितों के घरों में पता किया गया, लेकिन तीनों बच्चों का कहीं पता नहीं चला। ग्रामीणों के अनुसार, दर्शना के साथ गए दोनों दोस्त भी उसी दिन से गायब हैं। काफी तलाश के बाद परिजनों ने गुवा थाना में बुधवार को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत गुवा थाना या डायल 112 पर सूचित करें। सोशल मीडिया पर भी बच्चों की तस्वीर साझा कर मदद मांगी जा रही है।

गुमशुदा बच्चों के परिजन

सफायर प्रोजेक्ट पर विवाद जारी अवैध जमीन पर निर्माण का आरोप

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते प्रोजेक्ट के पार्टनर अनूप रंजन

JAMSHEDPUR : आदित्यपुर में हाल ही में शुरू किए गए द सफायर प्रोजेक्ट पर विवाद का साया मंडरा रहा है। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट जिस भूमि पर शुरू हो रहा है, उसमें समय कंस्ट्रक्शन की 3.97 एकड़ भूमि भी शामिल है। इस मामले में कोर्ट में केस कर दिया गया है। पुलिस और बैंक को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया है। आरोप है कि इस विवादित भूमि पर आदित्यपुर नगर निगम ने गलत तरीके से नक्शा भी पास कर दिया है। बताया जा रहा है कि बैंक ने भी इस जमीन पर 30 करोड़ रुपये तक का लोन दे दिया है। प्रोजेक्ट की शुरूआत के बीच इस तरह का विवाद शुरू हो जाने से अब खरीदारों के बीच भी उहापोह की स्थिति बन गई है। जमशेदपुर में बुधवार को समय कंस्ट्रक्शन के पार्टनर अनूप रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने आदित्यपुर के पास जमालपुर गांव में 3.97 एकड़ जमीन खरीदी थी। साल 2024 तक अनूप रंजन इस जमीन पर पूरी तरह काबिज थे। बाद में साल 2024 में इस भूमि पर द सफायर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन हुआ। तब से वहां बाउंसर लगा कर लगभग 14 एकड़ जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है।

दवा दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, दुकानें रहीं बंद

ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के खिलाफ केमिस्ट-ड्रगिस्ट ने दिखाई एकजुटता

PHOTON NEWS JSR: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर बुधवार को जमशेदपुर केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने साकची गोलचक्कर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले की अधिकांश दवा दुकानें बंद रहीं। दवा कारोबारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री, नकली दवाओं और नशीली दवाओं की बिक्री के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। केमिस्टों का कहना था कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स कंपनियां दवाओं की अनियंत्रित होम डिलीवरी के लिए कर रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य पर खतरा बढ़ सकता है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि दवाएं सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं हैं और इनके वितरण में सख्त चिकित्सकीय सत्यापन और लाइसेंस व्यवस्था जरूरी है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत तय नियामकीय व्यवस्था कमजोर हो रही है। नकली और नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की गई।

वक्ताओं ने कोविड महामारी के दौरान केमिस्टों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय दवा व्यवसायियों ने लोगों तक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की थी। इसके बावजूद ऑनलाइन दवा कारोबार से जुड़ी शिकायतों और अनियमितताओं पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन ने कहा कि छोटे केमिस्टों और उनके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार को जल्द सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। हालांकि हड़ताल शांतिपूर्ण रही और जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक व आपातकालीन दवा उपलब्ध कराकर मानवीय जिम्मेदारी भी निभाई गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पंकज छाबड़ा, महासचिव आशीष चटर्जी, कोषाध्यक्ष संजय कुमार कसेरा, उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह सोढ़ी, संयुक्त सचिव अनवर हुसैन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दविंदर वालिया समेत बड़ी संख्या में दवा व्यवसायी शामिल हुए।

साकची गोलचक्कर पर प्रदर्शन करते दवा दुकानदार ● फोटोन न्यूज

एक्शन रांची में आज पुलिस मुख्यालय में करीब 25 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की तैयारी

सारंडा में टूटा आतंक का गढ़, एक करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा पड़ा अकेला

PHOTON NEWS CHAIBASA : झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से लाल आतंक का गढ़ बना एशिया प्रसिद्ध सारंडा जंगल 26 साल बाद नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री के आदेश पर चल रहे नक्सल मुक्त अभियान का असर सारंडा में साफ दिखने लगा है। सुरक्षाबलों के लगातार दबाव, बड़े ऑपरेशन और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों के बाद एक करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा अकेला पड़ गया है। उसके दस्ते में भगदड़ मच गई है। सूत्रों के अनुसार सारंडा में चारों तरफ सुरक्षाबलों की घेराबंदी और लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे नक्सलियों से संगठन में हड़कंप है। कभी दहशत फैलाने वाले इनामी नक्सलियों में अब मौत का खौफ समा गया है। जंगल में बढ़ते दबाव और सुरक्षाबलों की सख्ती से घबराकर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े करीब 25 नक्सली एक-दो दिन में आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

रांची स्थित झारखंड पुलिस के मुख्यालय में इन नक्सलियों के औपचारिक आत्मसमर्पण की तैयारी शुरू हो चुकी है। ज्यादा संभावना है कि गुरुवार को ही समारोहपूर्वक ये नक्सली हथियार सहित समर्पण करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि लगातार बढ़ते दबाव के कारण मिसिर बेसरा भी सारंडा छोड़ चुका है। टूटते नेटवर्क और कमजोर होती पकड़ के बीच एजेंसियों को उम्मीद है कि वह भी जल्द मुख्यधारा में लौट सकता है।

पिछले कई महीनों से झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीमों ने सारंडा में लगातार सर्च ऑपरेशन, घेराबंदी और एंटी नक्सल अभियान चलाया। रणनीतिक कार्रवाई से नक्सली संगठन की कमर टूट गई है। एक समय नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाने वाला सारंडा अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट क्षेत्र बन चुका है। संगठन के भीतर बिखराव शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 25 नक्सलियों ने पुलिस को अपने हथियार भी सौंप दिए हैं, उन्हें अलग-अलग रांची लाया जा रहा है। इनमें करीब 10 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इधर सुरक्षा बलों का कहना है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास पैकेज और लगातार बढ़ते ऑपरेशन से नक्सलियों का मनोबल टूटा है। सारंडा में शांति बहाली के लिए यह निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। ग्रामीणों में भी उम्मीद जगी है कि अब जंगल में विकास की रोशनी पहुंचेगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में सात इनामी नक्सली (प्रभात मुखिया, गुलशन मुंडा, रेखा मुंडाइन, सागेन अंगरिया, करन तीव, सुलेमान हांसदा व बासुमति के अलावा बैजनाथ, रघु कायम, किशोर, रामदयाल, वंदना, बसंती, मुनी राम, अनिशा, बिरसा, लादू आदि) शामिल हैं।

फाइल फोटो

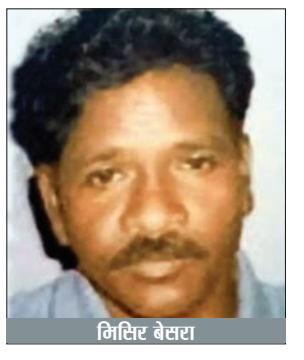
मिसिर बेसरा

हजारीबाग के ओपेन जेल में रखे जाएंगे

रांची में गुरुवार को समर्पण करने वाले नक्सली हजारीबाग स्थित ओपेन जेल में रखे जाएंगे। यहां उन्हें अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा मिलेगी। झारखंड पुलिस ने अपनी सरेंडर पॉलिसी में पिछले वर्ष ये बदलाव किया है, जिसके तहत अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली आम कैदियों के साथ जेल में नहीं रखे जाएंगे। ओपन जेल में नक्सलियों को कौशल योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत उन्हें रोजगार के विभिन्न गुर सिखाए जाएंगे। इससे वे जब जेल से बाहर निकलेंगे, तो उन्हें तुरंत रोजगार मिल सकेगा। वहीं, नक्सलियों पर घोषित इनाम की राशि भी उन्हीं को दी जाएगी।

BRIEF NEWS

भीमपुर में शराब के साथ दो तस्कर किए गए गिरफ्तार

SUPAUL : जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र में संध्या गश्ती के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 39.6 लीटर नेपाली शराब तथा 16.68 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इसके अलावा शराब के अवैध परिवहन में इस्तेमाल की जा रही दो मोटरसाइकिलों को भी विधिवत जब्त कर लिया गया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बिहार पुलिस ने लोगों से भी अवैध शराब कारोबार की सूचना पुलिस को देने की अपील की है, ताकि ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अपहरण व हत्या मामले में हिरासत में लिए गए दो किशोर

ARARIA : जिले में पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव से 19 मई अगवा किए गए 17 वर्षीय किशोर विशाल कुमार महतो की बेरहमी से हत्या कर देने की गुत्थी को महज दस घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझा लिया है । पुलिस ने घटना में शामिल मृतक के दो किशोर दोस्त को हिरासत में लिया है। एसपी जितेंद्र कुमार द्वारा घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मानवीय स्रोतों की मदद से त्वरित कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी किशोरों को पकड़ लिया। झाड़ियों से शव और गड्ढे से हथियार बरामद किए गए। किशोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चंडीपुर चराली के बांसबट्टी से मृतक विशाल कुमार महतो का शव बरामद किया।

जहरीला पदार्थ खाने से किशोरी की मौत

BHAGALPUR : जहरीला पदार्थ खा लेने के बाद मायागंज अस्पताल में इलाजरत किशोरी की बुधवार अहले सुबह होते हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका तीन बहनों और एक छोटे भाई में सबसे बड़ी थी और 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। किशोरी बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बीते 19 मई को घर के सभी सदस्य मकई काटने खेत गए हुए थे, जबकि किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान उसके पेट में दर्द हुआ। उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ पेट दर्द की दवा समझकर खा लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब परिजन घर लौटे तो पूछताछ में किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाने की बात बतायी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज लेकर पहुंचे।

नालंदा के नगरनौसा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कैला में मची अफरातफरी

छोले-चावल खाने से 60 बच्चे बीमार उल्टी-पेट दर्द से तड़पने लगे मासूम

AGENCY NALANDA : बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आयी है। जहां नगरनौसा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कैला में बुधवार को मिड-डे मील खाने के बाद करीब 50 से 60 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिसमें एक शिक्षक भी शामिल हैं। इस भोजन को खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) नगरनौसा और चंडी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से बीमार एक छात्रा को बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दोनों अस्पतालों में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। जैसे ही परिजनों को बच्चों के बीमार होने की जानकारी मिली, वे घबराए हुए अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।

चंडी रेफरल अस्पताल में भर्ती छात्रा व इलाज करते डॉक्टर

खाने में दिखी दवा जैसी गोली

अस्पताल परिसर में बच्चों के परिजनों की भारी भीड़ जुट गई। चिकित्सकों की टीम लगातार बच्चों के इलाज में जुटी रही। पांचवीं कक्षा की छात्रा अमृता कुमारी ने बताया कि मिड-डे मील में बच्चों को चावल और चने (छोला) की सब्जी परोसी गई थी। उसका आरोप है कि भोजन में किसी दवा जैसी गोली दिखाई दी थी। भोजन करने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी।

छात्रा अमृता कुमारी ने बताया रोजाना की तरह इस बार भोजन परोसने से पहले शिक्षकों द्वारा भोजन का स्वाद परीक्षण (टेस्टिंग) नहीं किया गया था। हालांकि बाद में अमरेश सर ने भोजन खाया, जिसके बाद उन्हें भी चक्कर आने लगा और उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा। अस्पताल में भर्ती बच्चों में अमृता कुमारी, अंकुश कुमार, अनुराधा कुमारी, तमन्ना, निशु, मुस्कान, कृति, ऋषि, आरती, सिमरन, खुशी, आदित्य, प्रियांशु, प्रिय, दीपक, प्रीति, डोली, सौरभ, किरण और राधा कुमारी समेत तीन दर्जन से अधिक अन्य बच्चे शामिल हैं। ग्रामीणों और अभिभावकों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता की समुचित जांच किए बिना बच्चों को खाना परोस दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानाध्यापिका रजनी कुमारी ने कहा मिड-डे मील में बच्चों को छोला और चावल परोसा गया था। भोजन शुरू करने के कुछ ही समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई बच्चों को उल्टी-दस्त होने लगे, जबकि कुछ बच्चे चक्कर खाकर बेहोश हो गए। स्थिति को देखते हुए तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि घटना की लिखित सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भोजन के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं और बच्चों के बीमार होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल अधिकांश बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि चिकित्सक सभी बच्चों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं, प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी की मानें तो बच्चों के मिड डे मील के खाने से बीमार पड़ने की सूचना पर जांच के लिए पहुंच चुके हैं। जो लोग इस लापरवाही में शामिल हैं। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल 6 बच्चे सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती हैं।

कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी, उद्योग खेल, सुरक्षा और हवाई सेवा से जुड़े कई बड़े फैसले

AGENCY PATNA : बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विकास, उद्योग, आधारभूत संरचना, सुरक्षा, खेल और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग के तहत मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अरावन (नालंदा) तथा मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कुदरा (कैमूर) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गयाजी

जिले के डोभी प्रखंड में आईएमसी, गयाजी के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जलाशय निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 428.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान मद की राशि जारी करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 747.97 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के अंतर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। वहीं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी), पटना तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित करने और 53 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा उससे संबद्ध संस्थानों में तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए 'यंग प्रोफेशनल चयन नीति-2026' को भी स्वीकृति प्रदान की। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने तथा आसूचना तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से विशेष शाखा में पुलिस महानिरीक्षक (सीमा) के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अरवल, औरंगाबाद तथा सहरसा जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए विभिन्न भूखंडों को खेल विभाग को निःशुल्क स्थायी अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

नवादा में ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर दो युवकों की मौत

NAVADA : बिहार में नवादा जिले के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर-सीतामढ़ी एसएच-103 सड़क पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेलवान गांव के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतरकर खेत में पलट गया, जबकि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के नीमा मुडहेता गांव निवासी 30 वर्षीय रंजीत कुमार एवं 35 वर्षीय समरेश यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक हिसुआ बाजार से अपने गांव लौट रहे थे, तभी बेलवान गांव के पास यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीतामढ़ी थाना की 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

NEWS BOX

सरयू नदी के रामघाट पर डूबने से युवक की मौत, तीन दोस्त बचे

AGENCY SARAN : मांझी रामघाट पर दोपहर सरयू नदी में नहाने के दौरान दाउदपुर निवासी आशिक अली गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से उसके तीन अन्य दोस्त बाल-बाल बच गए। चारों दोस्त करीब 11 बजे से नदी में नहा रहे थे। दोपहर सवा 12 बजे के आसपास जब एक दोस्त किशन कुमार गुप्ता डूबने लगा, तो आशिक उसे बचाने आगे बढ़ा। किशन को तो बचा लिया गया लेकिन आशिक खुद गहरे पानी में समा गया। घटना की सूचना पर अंचलाधिकारी सौरभ अभिषेक और मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक के पिता साइकिल पर कपड़े की फेरी लगाते हैं और आशिक दो भाइयों में बड़ा था। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। बता दें कि मंगलवार को भी इसी घाट पर रील, वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक डूबने से बचा था। लगातार हो रहे इन हादसों से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने और रामघाट पर स्नान को तत्काल प्रतिबंधित करने की मांग की है।

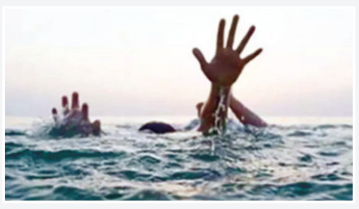

तीन चोर किए गए अरेस्ट, 503 ग्राम चांदी के जेवर बरामद

AGENCY SIWAN : पचरुखी थाना क्षेत्र के मल्लुपुर गांव में घर में घुसकर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए 503 ग्राम चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 3 मई 2026 को मल्लुपुर गांव निवासी ताराचंद विष्णु मौर्या ने पचरुखी थाना में आवेदन देकर बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर ज्वेलरी की चोरी कर ली है। मामले में पचरुखी थाना में बीएनएस की धारा 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी अनुसंधान एवं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नारायणपुर नहर पुल के समीप से तीन अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लुपुर गांव निवासी आर्यन कुमार, पिता जयराम राम, सन्नी कुमार, पिता रामबहादुर सिंह एवं अभिषेक कुमार, पिता हरेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई 503 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

सुपौल में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक

AGENCY SUPAUL : सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में मंगलवार को धान अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सावन कुमार ने की। बैठक में उप विकास आयुक्त सारा अशरफ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक राजीव कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी रामबाबू सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं विभिन्न राइस मिलों के संचालक और प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राइस मिलों द्वारा सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) जमा करने की धीमी प्रगति और विलंब पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी मिलरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 जून 2026 से पहले निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर बिहार राज्य खाद्य निगम को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षक भर्ती परीक्षा को ले प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने दिया जल्द तिथि घोषित करने का आश्वासन

- छात्र नेता रिंकल यादव को प्रदर्शन स्थल से घसीटते हुए हिरासत में लिया
- पुलिस ने कहा- स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए की गई आवश्यक कार्रवाई

AGENCY PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की टीआरई-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा) की वैकेंसी जल्द जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को राजधानी पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार-बार सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। छात्रों का आरोप है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसी नाराजगी के बीच आंदोलनकारियों ने थाली और बेलन के साथ सड़क पर उतरकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को 'नींद से जगाने' की चेतावनी दी। प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले पुलिस ने छात्र नेता रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया।

मंत्री ने की स्थिति को संभालने की कोशिश

इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इसका विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि मंत्री ने वैकेंसी जारी होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी जानबूझकर नहीं की जा रही है और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आंदोलन के पीछे कुछ बाहरी तत्वों के सक्रिय होने की आशंका भी जताई।

छात्रों का नामांकन नहीं होने से अभिभावकों में बढ़ा आक्रोश

BHAGALPUR : जिले के इंटर स्तरीय पंचानन झा उच्च विद्यालय बैजानी में नामांकन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अपने बच्चों का नामांकन नहीं होने से नाराज अभिभावकों ने बुधवार को स्कूल पहुंचकर विरोध जताया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे पहले से इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इसके बावजूद इस बार नामांकन नहीं लिया जा रहा है। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि अचानक बदले नियमों की वजह से कई छात्र-छात्राओं का नामांकन अटक गया है। इससे बच्चों के भविष्य को लेकर परिवार चिंतित हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से सीट बढ़ाने और सभी योग्य बच्चों का नामांकन लेने की मांग की।

मोतिहारी में प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा मामले में तीन शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

AGENCY MOTIHARI : बिहार के मोतिहारी में गजब का खेल चल रहा है। जेल में बंद बालिग अपराधियों को फर्जी दस्तावेज के सहारे नाबालिग साबित करने वाले गिरोह का पदार्फाश हुआ है। नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र बनाकर अपराधियों को किशोर न्याय अधिनियम का लाभ दिलाते थे।

पूरा मामला चिरैया थाना कांड संख्या-126/22 के अभियुक्त भोला कुमार उर्फ भोला साह से जुड़ा है। अभियुक्त को नाबालिग साबित करने के लिए किशोर न्याय परिषद, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के न्यायालय में फर्जी स्कूल

सर्टिफिकेट पेश किए गए थे। दस्तावेजों पर संदेह होने के बाद परिषद ने नगर थाना में आवेदन दिया।

आवेदन मिलते ही नगर थाना में कांड संख्या-453/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस ने गहन छानबीन की। जांच में सामने आया कि इस फजीर्वाड़े के पीछे तीन शिक्षकों का गिरोह काम कर रहा था। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का पदार्फाश कर सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि परेवा निवासी सरकारी शिक्षक सुबोध कुमार पाठक, एक अन्य शिक्षक भोला कुमार और एक सरकारी शिक्षिका ने मिलकर यह साजिश रची थी। इन तीनों ने फर्जी स्कूल प्रमाणपत्र तैयार किए। दस्तावेजों में अभियुक्त की उम्र कम दिखाकर उसे नाबालिग साबित करने की कोशिश की गई, ताकि उसे जेल की बजाय रिमांड होम भेजा जा सके।

मामले की पुष्टि होते ही नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने तीनों आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया।

कृषि उद्यान व वानिकी महाविद्यालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड वेदर कम सॉयल सेंसर यूनिट स्थापित

पूर्वी चंपारण में अब सेंसर से होगी फसलों की निगरानी

AGENCY EAST CHAMPARAN : अब सेंसर से फसलों की निगरानी होगी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय पीपराकोठी के इंस्ट्रक्शनल फार्म में आधुनिक कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड वेदर कम सॉयल सेंसर यूनिट स्थापित की गई है। यह यूनिट तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा, वायु दाब, पवन गति, मिट्टी की नमी, मिट्टी का तापमान तथा विभिन्न रोगों के पूवार्नुमान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां रियल टाइम में उपलब्ध कराएगी। इससे वैज्ञानिक फसल प्रबंधन एवं प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा

सेंसर फसल तकनीक की जानकारी लेते डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी

मिलेगा। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. कुंदन किशोर ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए कृषि एवं उद्यानिकी में आधुनिक तकनीकों का उपयोग समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने कहा कि यह यूनिट विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि तकनीकों का व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके माध्यम से छात्र मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, रोग पूवार्नुमान, सिंचाई निर्धारण, फसल स्वास्थ्य निगरानी तथा स्मार्ट फार्मिंग तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे। यह यूनिट मोबाइल तकनीक से भी जुड़ी हुई है, जिसके जरिए सभी आवश्यक जानकारियां सीधे मोबाइल फोन पर प्राप्त की जा सकती हैं। किसान और शोधकर्ता कहीं से भी अपने मोबाइल पर खेत की वास्तविक स्थिति देख सकेंगे। इसके आधार पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई, उर्वरक एवं कीटनाशी या फफूंदनाशी दवाओं के प्रयोग को लेकर त्वरित और सटीक निर्णय लिया जा सकेगा। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत होगी तथा फसल प्रबंधन अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनेगा। फल, सब्जी और पुष्प फसलों में मौसम आधारित प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तापमान, आर्द्रता और मिट्टी की नमी में होने वाले परिवर्तन सीधे फसल की वृद्धि, गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह सेंसर यूनिट समय रहते आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराकर फसलों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने में सहायक सिद्ध होगी।

जीविका हाट का हुआ उद्घाटन, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

SAHARSA : जिले के सलखुआ प्रखंड के चानन पंचायत में बुधवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार द्वारा मनरेगा के सौजन्य से निर्मित जीविका हाट का उद्घाटन किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर उप विकास आयुक्त ने कहा कि जीविका हाट ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके उत्पादों को स्थानीय बाजार उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने जीविका दीदियों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी आजीविका गतिविधियों को और मजबूत करने का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने 15 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

AGENCY PATNA : बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में बुधवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सिंचाई भवन स्थित विभागीय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 15 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें छह नवनियुक्त सहायक अभियंता, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त छह निम्नवर्गीय लिपिक तथा तीन कार्यालय परिचारी शामिल हैं। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वे जल संसाधन विभाग परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग

का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है, जहां किसानों और आम लोगों को सिंचाई तथा बाढ़ सुरक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में विभागीय कर्मियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विभाग की छवि उसके क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली, सक्रियता और ईमानदारी से बनती है। इसलिए सभी नवनियुक्त कर्मियों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

स्वदेशी शक्ति से वैश्विक होता भारत का रक्षा क्षेत्र

भारत का रक्षा क्षेत्र आज वहां आ पहुंचा है, जहां तकनीक, अनुसंधान और स्वदेशी क्षमताएं राष्ट्रीय शक्ति का नया आधार बनती जा रही हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने रक्षा अनुसंधान को नीति के केंद्र में स्थापित किया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था अधिक सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर बन रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा व्यक्त विचार इस दिशा में स्पष्ट संकेत देते हैं कि आने वाला समय तकनीकी श्रेष्ठता का होगा और भारत इस दौड़ में पीछे रहने वाला देश नहीं है। वस्तुतः आज केंद्र सरकार द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना एक दूरदर्शी कदम माना जा सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा अब तक 2200 से अधिक तकनीकों का उद्योगों को हस्तांतरण इस बात का प्रमाण है कि देश में शोध और उत्पादन के बीच मजबूत पुल तैयार हो चुका है। इस प्रक्रिया ने रक्षा उत्पादन को गति दी है और निजी क्षेत्र को भी नए अवसर प्रदान किए हैं। अनुसंधान पर निरंतर ध्यान बनाए रखना भविष्य के युद्धों में बढ़त दिलाने वाला कारक बन सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों, अकादमिक संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित किया जाना एक क्रांतिकारी पहल है। इन संस्थाओं द्वारा 4500 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग यह दशार्ता है कि देश में नवाचार की ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। इससे एक ओर जहां नई तकनीकों का विकास संभव हुआ है, वहीं युवाओं को भी रक्षा क्षेत्र में योगदान देने का अवसर मिला है। नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति के तहत शुल्क समाप्त करना उद्योगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ है। इससे विकास और उत्पादन में साझेदारी को बढ़ावा मिला है। साथ ही पेटेंट्स को मुफ्त उपलब्ध कराने की नीति ने तकनीकी विकास को नई गति दी है। परीक्षण सुविधाओं को उद्योगों के लिए खोलना भी सहयोगात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यही कारण है कि भारत अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाइपरसोनिक हथियार, क्वांटम तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तकनीकें भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेंगी। इन क्षेत्रों में निवेश और अनुसंधान भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। हमने पिछले साल देखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में स्वदेशी तकनीकों का सफल उपयोग देश की बढ़ती सैन्य क्षमता को दशार्ता है। आकाशतीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही कहना होगा कि भारत के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन का 1.54 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। रक्षा निर्यात का 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले एक दशक में 174 प्रतिशत की वृद्धि और निर्यात में कई गुना विस्तार देश की बदलती पहचान को दशार्ता है, जिसमें रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का योगदान इस क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को दर्शा रहा है। अब रक्षा निर्माण सरकारी संस्थानों की पहुंच से आगे उद्योगों और स्टार्टअप्स की सक्रियता में एक व्यापक इकोसिस्टम बन चुका है। स्वभाविक तौर पर इससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा मिला है। आज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एडीआईटीआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी योजनाएं रक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। इन पहलों ने युवाओं और उद्यमियों को रक्षा तकनीकों के विकास में भाग लेने का अवसर दिया है। इससे देश में नवाचार की संस्कृति मजबूत हो रही है। ऐसे में यह भी ध्यान में आता है कि भारत का लक्ष्य अब तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है, जिसमें महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास, स्वामित्व और संरक्षण देश के भीतर ही हो। क्वांटम-सिक्योर कम्युनिकेशन जैसी उपलब्धियां इस दिशा में बड़ी प्रगति को दशार्ती हैं। यह क्षमता भविष्य के युद्धों में निर्णायक साबित हो सकती है। बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये का आवंटन सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाएगी। अतः हम सभी के लिए आज गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है, जहां आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक पहचान एक साथ आकार ले रही हैं। यह परिवर्तन हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह तो हम सभी जानते हैं कि देश का रक्षा क्षेत्र सुरक्षा का प्रतीक है, किंतु कहना होगा कि इस दिशा में हो रहे नवाचार आज शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं, जो हर भारतीय को आशा और उत्साह से भर रहे हैं।

मोदी सरकार में भारत की आर्थिक मजबूती के कई तथ्य

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई महंगाई, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति, बैंकिंग संकट और हालिया वैश्विक शुल्क दबाव जैसे अनेक संकटों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रही। वस्तुतः भारत की आर्थिक मजबूती को केवल मूडीज की रिपोर्ट तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे अनेक ऐसे ठोस तथ्य हैं, जो यह बताते हैं कि बीते वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत आधार तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक नीतियों में जो स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि दिखाई दी, उसी का परिणाम है कि आज भारत वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में शामिल हो चुका है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत की मौद्रिक नीति को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई नियंत्रण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई दोहरे अंक तक पहुंच गई, मगर भारत ने उसे नियंत्रित दायरे में बनाए रखा। निवेशकों का भरोसा इसी कारण लगातार बढ़ा है। भारत की दूसरी बड़ी ताकत उसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है।

दुनिया इस समय आर्थिक अस्थिरता, युद्धों, ऊर्जा संकट, महंगाई और वैश्विक व्यापारिक तनावों के दौर से गुजर रही है। कोविड महामारी के बाद अनेक विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब भी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। ऐसे समय में भारत का लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत है। यही कारण है कि आज भारत को दुनिया की सबसे भरोसेमंद उभरती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि भारत ने हर बड़े वैश्विक आर्थिक झटके के बीच उल्लेखनीय स्थिरता दिखाई है। कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुई महंगाई, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति, बैंकिंग संकट और हालिया वैश्विक शुल्क दबाव जैसे अनेक संकटों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रही। वस्तुतः भारत की आर्थिक मजबूती को केवल मूडीज की रिपोर्ट तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे अनेक ऐसे ठोस तथ्य हैं, जो यह बताते हैं कि बीते वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत आधार तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक नीतियों में जो स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि दिखाई दी, उसी का परिणाम है कि आज भारत वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में शामिल हो चुका है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत की मौद्रिक नीति को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई नियंत्रण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई दोहरे अंक तक पहुंच गई, मगर भारत ने उसे नियंत्रित दायरे में बनाए रखा। निवेशकों का भरोसा इसी कारण लगातार बढ़ा है। भारत की दूसरी बड़ी ताकत उसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। यह भंडार आर्थिक सुरक्षा कवच है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आने पर यही भंडार रुपये को स्थिर रखने और आयात जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अनेक देशों की मुद्राएं वैश्विक दबाव में तेजी से कमजोर हुईं, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक संतुलित बनी रही। वहीं, भारत की घरेलू मांग भी उसकी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। देश की विशाल आबादी और बढ़ता मध्यम वर्ग आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। यही कारण है कि वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत में खपत बनी रही। हाउसिंग, वाहन, डिजिटल सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ती दिखाई दी। वित्त वर्ष 2025-26 के बैंकिंग आंकड़े इस मजबूती को और स्पष्ट करते हैं। 15.9 प्रतिशत की क्रेडिट ग्रोथ यह संकेत देती है कि उद्योग, व्यापार और उपभोक्ता क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। कुल कर्ज 212.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना आर्थिक विस्तार का बड़ा संकेत है। सेवा क्षेत्र में 19 प्रतिशत की क्रेडिट वृद्धि बताती है कि भारत का सर्विस सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उद्योग क्षेत्र में भी कर्ज वितरण लगभग दोगुना होकर 15 प्रतिशत तक पहुंचा है, जो विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार का संकेत देता है। विशेष रूप से माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि यह दशार्ती है कि आर्थिक विकास अब केवल बड़े शहरों या कॉरपोरेट समूहों तक सीमित नहीं रहा। छोटे उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को भी वित्तीय मजबूती मिल रही है। यही वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकेत भी उत्साहजनक हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 15.7 प्रतिशत की क्रेडिट ग्रोथ बताती है कि गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। कृषि क्षेत्र में तकनीक, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण आधारभूत संरचना पर ध्यान देने का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। टैक्स संग्रह के आंकड़े भी आर्थिक मजबूती का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि बताती है कि आर्थिक गतिविधियां स्थिर हैं और कर अनुपालन बेहतर हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी कंपनियों की बेहतर आय और कारोबार विस्तार की ओर संकेत करती है। इसके साथ आज जो दिख रहा है, वह यह भी है कि देश में डिजिटल भुगतान और तकनीक आधारित प्रशासन ने कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। व्यक्तिगत ऋणों में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि यह दिखाती है कि आम नागरिकों का आर्थिक विश्वास मजबूत हुआ है। लोग घर खरीद रहे हैं, वाहन ले रहे हैं और निवेश करने का साहस दिखा रहे हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। वास्तव में भारत की आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार नीतिगत स्थिरता है। पिछले वर्षों में आधारभूत संरचना निर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जीएसटी, बैंकिंग सुधार और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। वस्तुतः आज भारत को लेकर इसलिए ही दुनिया की अनेक शक्तिशाली संस्थाएं-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसएंडपी और फिच भी भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं को सकारात्मक मान रही हैं। स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक मजबूती किसी एक रिपोर्ट या एजेंसी के मूल्यांकन का परिणाम नहीं है। इसके पीछे मजबूत नीतियां, विशाल घरेलू बाजार, बढ़ता निवेश, बैंकिंग स्थिरता, डिजिटल क्रांति, विदेशी मुद्रा भंडार और जनविश्वास जैसे अनेक ठोस आधार मौजूद हैं। यही कारण है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व की सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहा है।

अपना अंत स्वयं लिखती है हर सत्ता

पश्चिम बंगाल की राजनीति पाप का एक ऐसा घड़ा भर रही थी, जो कब का लबालब हो चुका था। उसे इतनी ही जोर से फूटना ही था। अब तक तीन ताकतें ही बंगाल में काबिज रहीं। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और फिर टीएमसी। तीनों ही अलग नहीं हैं। तीसरी ताकत पहली से टूट कर ही बनी। पहली और दूसरी की यारी ईमान पर टिकी थी। ईमान का यह तत्व टीएमसी में जन्मजात था। ईमान को मजबूत बताने की होड़ तय करती थी कि घुसपैठियों के प्रति कौन कितना दयावान है। इन नतीजों ने देश के दूसरे हिस्सों में पहले ही दिवालिया हो चुके मजहबी वोटबैंक की एक और मजबूत ब्रांच को उजाड़ दिया है। कम्युनिस्टों के लंबे कब्जे में आने के बाद कोलकाता धीरे-धीरे एक कबाड़खाना ही बन गया। नाजायज कब्जों और वसूली का ऐसा मॉडल शायद ही देश में कहीं हो। शानदार शोरूम वाले भीड़ भरे बाजारों के चौड़े फुटपाथ अतिक्रमण में ऐसी दुकानों को दे दिए गए, जिनके मुंह शोरूम की तरफ थे। पूरे कोलकाता में यह एक समांतर अर्थव्यवस्था है, जिसकी सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ से खिसक कर टीएमसी के हाथ में आ गई, क्योंकि हारने के बाद गलियों के सारे कम्युनिस्ट गिरोह टीएमसी की तगाड़ी उठाने लग गए। कुछ नहीं बदला। पोरिबर्तन केवल एक नारा साबित हुआ था। अंग्रेज आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर आज के कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग से होकर तीन-चार किलोमीटर चारों ओर के बाजारों और फुटपाथों पर घूमकर देखें तो एक स्वर कहेंगे- ये इसी लायक थे। केवल कोलकाता ही नहीं, दूसरे शहरों में भी बंगाल विचित्र है। रेलवे स्टेशनों पर आपने कब्जे बाहर देखे होंगे, मगर स्टेशन मास्टर के ऑफिस से सटकर दोनों तरफ प्लेटफॉर्मों पर रेल के डिब्बों की तरफ खुलती दुकानों का बाजार देश में कहीं नहीं देखा होगा। रेलवे की जमीन पर प्लेटफॉर्मों पर कब्जों का यह अनूठा प्रयोग केवल बंगाल में ही संभव हुआ। रेलमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी के पोरिबर्तन में यह कोई विषय ही नहीं था। नशे के फैलाव के कारण पंजाब को एक फिल्म में उड़ता हुआ पंजाब कहा गया। बंगाल की कई यात्राओं के बाद मैंने बहुत दुख से इसे सड़ता हुआ बंगाल कहा था। ये नतीजे बता रहे हैं कुछ उम्मीद बाकी है। वह पूरी तरह सड़ा नहीं है। जनवरी में मेरा वेलूर मठ और दक्षिणेश्वर जाना हुआ। पहले भी गया हूं और कोलकाता के वे स्थान, जहां स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां ताजा हैं। महर्षि अरविंदो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिमचंद्र, शरतचंद्र के अलावा बड़ा बाजार की पुरानी इमारतों के बीच ठाकुरबाड़ी, जहां गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के परिवार की अनगिनत यादें हैं। हर बार मैं सोचता रहा कि ये विभूतियां अगर आज के बंगाल की हालत देखें तो क्या सोचेंगी। इतने गहरे सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों वाले पुनर्जागरण की भूमि को यह कौन-सा अभिशाप जकड़े हुए है। बंकिम अपनी मातृभूमि का वंदन करने के लिए उस सरहद के किस तरफ मुंह करेंगे, जिसकी दूसरी ओर से आने वाले अपराधी घुसपैठिए इस तरफ के बंगाल का राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र उलटने में लगे हैं और उन्हें पोसने वाले यहाँ वंदनवार सजाए हुए हैं। उन्हें कोलकाता से ढाका तक देखना होगा कि डायरेक्ट एक्शन से रक्तरंजित उनकी मातृभूमि किस बुरे हाल से गुजरी है और रक्तबीजों की अमरबेल कहां-कहां लिपटी पड़ी है। अतीत में झांकना हर समय सुखद नहीं होता मगर वह ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ निष्कर्ष हमें जरूर देता है। कोई भी राजनीतिक दल सीटों की संख्या के हिसाब से सिमटना और सिकुड़ना बाद में शुरू करता है, पहले वह वैचारिक रूप से दिवालिया होता है। विचार ही राजनीति में महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद का इतिहास हर दशक में हर राज्य में अपनी परतें उघाड़ता है। स्वाधीनता संघर्ष की खुमारी सत्ता में जितना टिकाए रख सकती थी, टिकाया मगर भारत के लिए कोई नया और मौलिक विचार उस दौर की राजनीति पैदा नहीं कर सकी। सत्ता ही विचार में थी, जो केंद्र के बाद राज्यों में भी परिवार केंद्रित होती गई। इसलिए आपातकाल तक आते-आते सब बिखरने लगा। विचारहीन राजनीति कोई सबक सीखने लायक भी नहीं बचती। बूढ़े दरख्त की सूखी शाख ठूंठ हो जाती हैं। हरी कोंपले वहाँ नहीं आती। रात के वक्त वहाँ बैठे उल्लू सिर घुमाकर आँखें चमकाते हैं। आजादी के बाद हुए हजारों छोटे-बड़े आंदोलनों को देखें। ऐसे आंदोलन जिन्होंने देश की राजनीति को स्थाई रूप से प्रभावित और परिवर्तित किया। अयोध्या के राममंदिर आंदोलन को आप किस कसौटी पर रखेंगे। एक विचार को लेकर कुछ नेता एक नई-नई पार्टी बनाकर देश में घूमते-भटकते रहे। उन्हें दकियानूसी कहा गया, जिनका आधुनिक विश्व की जरूरतों से कोई सरोकार नहीं था। वे बार-बार की हार से भी नहीं हारे। हार-हारकर भी अपने विचार पर टिके रहे-तुष्टिकरण का विरोध, कश्मीर में 370, समान नागरिक संहिता और अयोध्या में एक मंदिर। सब हंसते थे। गरियाते थे। मजाक उड़ाते थे, मगर उनके पास कोई दूसरा मौलिक विचार भी नहीं था। दिल्ली, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, चेन्नई, चंडीगढ़ में सत्ता परिवारों के पास थी। विचारहीन पारिवारिक रियासतें, जिनके लिए सत्ता ही विचार थी। बंगाल पर लौटते हैं। बंगाल एक कठिन और जटिल राजनीतिक भूमि है। दशकों की बिगड़ी आदतें हैं, जो रक्त में समा गई हैं और इनका शुद्धिकरण सरल नहीं है। दो सौ पार का यह परिणाम बेचैन बंगालियों की अनंत अपेक्षाओं का एक भारी-भरकम बोझ भी है, जो अब नए कंधों पर है। असंभव को संभव बनाना भी केवल राजनीति से ही संभव है। बिहार, यूपी और असम में एक जैसी समस्याओं का विस्तार है, जिनमें डेमोग्राफी सबसे चिंतानक है। वोट बैंक बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति ने इस घुन को लगभग पूरे देश में फैलने के लिए अनुकूल जमीन तैयार की है, जिसके बुरे परिणाम पूरे देश में उबलते देखे जाते हैं। बंगाल के नए नेतृत्व को वास्तविक परिवर्तन के लिए असम, यूपी और उत्तराखंड के तजुर्बों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। परिणाममूलक परिवर्तन के कुछ सूत्र हेमंता बिस्वा सरमा से लेने ही पड़ेंगे, कुछ पाठ योगी आदित्यनाथ से सीखने होंगे और थोड़ा सा पुष्कर सिंह धामी की पहली कक्षा में झांकते हुए आगे बढ़ना होगा।

Social Media Corner

सच के हक में...

रोम पहुंचते ही मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रिभोज करने का अवसर मिला, जिसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। आज होने वाली हमारी वार्ता के लिए मैं उत्सुक हूँ, जिसमें हम भारत और इटली के बीच मित्रता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे। मैंने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मिलकर एक संपादकीय लेख लिखा है जिसमें बताया गया है कि भारत-इटली संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। हमारी साझेदारी नवाचार, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण से प्रेरित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के साथ कथित शारीरिक शोषण और गर्भवती होने का मामला बेहद गंभीर, शर्मनाक और न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। जानकारी के अनुसार महिला नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और पिछले महीने उसकी प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में यह स्पष्ट संकेत देता है कि जेल परिसर के भीतर ही उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, जिसकी निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है। और भी चिंताजनक बात यह है कि दो-तीन दिन पूर्व महिला को प्रेग्नेंसी जांच के लिए निजी लैब भेजा गया, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे संवेदनशील मामलों में सिविल सर्जन की अनुमति तथा सरकारी अस्पताल, विशेषकर रिम्स, में जांच और उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पूरे मामले को दबाने और सबूत प्रभावित करने की आशंका और गहरी हो जाती है। यदि आरोप सत्य हैं, तो यह केवल एक महिला कैदी के साथ अपराध नहीं, बल्कि न्यायिक हिरासत में राज्य की जिम्मेदारी और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

कृषि को संकट से बचाने की चुनौती

इन्वेस्टमेंट इनफॉरमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर मानसून, अल नीनो के प्रभाव और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस वर्ष कमजोर मानसून से भारत में कृषि की पैदावार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने और विकास दर में कमी की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने भी अल नीनो के कारण इस साल सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। यह पूवार्नुमान पिछले 26 वर्षों में मानसून का सबसे कम शुरूआती अनुमान है। इससे देश में कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर असर पड़ सकता है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में भी इसी तरह का पूवार्नुमान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 75 प्रतिशत वर्षा पर आधारित मानसून सीजन (जून से सितंबर) में 94 प्रतिशत वर्षा हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि सामान्य से कम मानसून वाले वर्षों में जब बारिश का समय, वितरण और फैलाव लगभग समान रहा, तब खरीफ के उत्पादन में अधिक कमी नहीं हुई, किंतु गैर-सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए जोखिम पैदा हुआ। दलहन और तिलहन का कम उत्पादन खाद्य महंगाई पर असर डाल सकता है। एक ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया संघर्ष से महंगे उर्वरक, महंगे तेल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से खेती की लागत बढ़ी है, तब कमजोर मानसून से न केवल किसानों और कृषि पर, वरन आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है। इससे पेयजल समस्या की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। गत वर्ष के मानसून सीजन में अच्छी बारिश के कारण जलाशयों में पर्याप्त पानी है, लेकिन अब इस साल अल नीनो के खतरे और कमजोर मानसून की आशंका से जलाशय के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पानी का स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है। नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 प्रतिशत ही सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार, गेहूं की लगभग 74 प्रतिशत और धान की 65 प्रतिशत खेती वाले क्षेत्र पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और उद्योगीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मानसूनी वर्षा पर निर्भरता काफी बढ़ी है। यह परिदृश्य देश में अभी सहज स्थिति वाले कृषि क्षेत्र के समक्ष एक नई चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। इस वर्ष सामान्य से कम मानसून और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए कई बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अभी से ही जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में विविधतापूर्ण जलवायु है। देश कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के मामले में समृद्ध है। अतः भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश में अभी भी अनाज, दलहन तथा तिलहन का उत्पादन मौसम पर निर्भर होता है। ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार स्थितियों का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करनी चाहिए। हमें कमजोर मानसून के पूवार्नुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण मजबूत करना चाहिए। वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 17.41 करोड़ टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 17.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में एक बड़ी छलांग है। पिछले वर्ष खरीफ उत्पादन 16.94 करोड़ टन था, जिसमें इस बार लगभग 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रबी उत्पादन पिछले वर्ष 16.91 करोड़ टन था, जिसमें इस बार 3.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच भारत में अनाज का यह रिकार्ड उत्पादन एक सुरक्षा कवच की तरह है।

सालाना स्वास्थ्य जांच

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एलान किया है कि नए श्रम संहिता में मौजूदा प्रावधानों के तहत 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के कामगारों को मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच मुहैया कराई जाएगी। इस कार्यक्रम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जरिए अमल में लाया जाएगा। जहरीले रसायनों को संभालने या भारी मशीनरी चलाने जैसी खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कामगारों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। जांच के दौरान अगर किसी बीमारी का पता चलता है, तो ईएसआईसी के अस्पताल और औषधालयों में मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। भारत में पहले से ही कामगारों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ दायित्व लिखित रूप में मौजूद हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948 (सिर्फ कारखानों के भीतर), ईएसआई अधिनियम, 1948 और पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों (ओएसएच) संहिता, 2020 के तहत प्रावधान शामिल हैं। इस नए कार्यक्रम का वित्तपोषण पर्याप्त संसाधनों से लैस ईएसआई फंड के जरिए किया जाएगा। हालांकि, सरकार अभी भी पीएमजेएवाई में सूचीबद्ध सुविधाओं के जरिए उपलब्ध बिस्तरों और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल, संचालन से जुड़े साक्ष्य बताते हैं कि बीमाकृत कामगार ही इसके मुख्य लाभार्थी होंगे। यह पहल सराहनीय तो है, लेकिन इसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल, 94 करोड़ कामगारों में से केवल लगभग 31 करोड़ कामगार ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और कई राज्यों में ईएसआईसी के साथ इसका समन्वय अभी भी शुरूआती चरण में ही है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यह भी बताने में नाकाम रहे कि अगर कपड़ा कारखाने में या घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली किसी महिला का कोई नियोक्ता नहीं है, तो वह लंबी मातृत्व अवकाश का लाभ कैसे उठा सकेगी।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The return of great power bargaining

President Donald Trump returned to China this week, over eight years after his last visit in November 2017. The symbolism is hard to miss. Between 1972 and 2017, every US President made the journey to Beijing with the conviction that strengthening ties with China was not incongruous with preserving American dominance. Joe Biden broke with that tradition. His administration called China out as the greatest challenge to American power because it was seeking to reshape the global order built by America, and framed the rivalry as between democracy and autocracy. Trump's return to Beijing closes that chapter. Statements from Washington, including the National Security Strategy released last November and during Trump's visit, suggest that the US has reverted to the path of managing the rise of a rival through accommodation.However, it might be a mistake to presume that Trump went to China with the weaker hand. Both parties came to the table with some leverage, but both are also in pain. The bruising tariff war in 2025 has damaged both economies. It is true that America's trade deficit with China stubbornly remains at $350 billion, but China's access to American markets is also reducing. The last time Trump was in Beijing, the near-universal expectation was that China would overtake the US in GDP terms by the mid-2020s, but the Chinese economy ($21 trillion) is still stuck at two-thirds the size of the US's GDP ($32 trillion). Between the two visits by Trump, China's share of global manufacturing has increased from 20 percent to 29 percent, whereas the US's share has further declined to 16 percent. Yet, in technology, the Americans maintain the lead and still have the ability to impede China's scientific progress due to their dominance in high-end chip design and manufacturing. And, despite persistent Chinese efforts to conduct more trade, including in oil and gas, in the renminbi, the dollar is still king.

In terms of the war in the Persian Gulf, Trump's inability to end it on purely American terms may be satisfying, but a prolonged closure of the Hormuz Strait is not in China's interest. Its studied non-intervention at any level suggests that it is not yet a match for US global power. It would be more accurate to say that the two leaders met on terms more equal than when Trump last called on President Xi Jinping in 2017, but not as complete equals.

Notwithstanding this, during Trump's visit, Xi made every effort to put the relationship on par with that of two peers without equal. References to creating a 'new paradigm of major country relations', underscoring how this relationship was the most significant one globally, and even Xi's reference to the 'Thucydides Trap'—the Greek theory suggesting that a rising power threatens to displace an established dominant power—were intended to reinforce that point. China might not have explicitly mentioned a G-2, but given that Trump has used this definition earlier, its choice of phrases suggests it is not averse to the idea.The optics suggest that neither side wishes to return to the mutually damaging tit-for-tat downward spiral of the previous year. Each party had its bucket list. China was seeking tariff relief, the softening of US sanctions against

India, UAE navigate shifting sands

PM Modi's visit to Abu Dhabi was largely aimed at boosting President Sheikh Mohamed's morale

PRIME Minister Narendra Modi's May 15 stopover in the United Arab Emirates (UAE) coincided with the conclusion of US President Donald Trump's visit to China and the BRICS foreign ministers' meeting in New Delhi. These developments took place under the shadow of the war in West Asia.

Two questions arise: How did the UAE get embroiled in the ongoing conflict? What was the purpose of PM Modi's meeting with President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (popularly known as MbZ)?

Ever since seven emirates formed the UAE in 1971, it has been stuck between Iran, covering the entire northern Gulf coast, and Saudi Arabia — a self-proclaimed regional and Islamic power — in the south. In the 1950s, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan — who later became Abu Dhabi's ruler and the UAE's first President — confronted the Saudis when they offered him a bribe to grab the Buraimi belt, which was believed to have huge oil deposits. He led Abu Dhabi's forces in ejecting them.Sheikh Zayed used native wisdom to steer the UAE towards prosperity by avoiding entanglement in regional disputes like the Iran-Iraq war and the occupation of Kuwait by Iraqi President Saddam Hussein. After Sheikh Zayed's death in 2004, his younger son Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan first became the Crown Prince and then the de facto ruler when the elder son, Sheikh Khalifa, suffered a stroke in 2014. Sheikh Mohamed formally assumed presidency in 2022.Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman had a parallel rise, assuming office in 2017. President Sheikh Mohamed took him under his wing, especially protecting him from US ire over journalist Jamal Khashoggi's 2018 killing in Turkey.However, their relationship soured when US President Trump came up with the 2020 Abraham Accords. They envisaged an Arab-Israel alliance to contain Iran, with the Palestinian issue sidelined. While the UAE promptly signed alongside Bahrain, the Saudis demanded that Israel first specify the path to Palestinian statehood. Trump withdrew the US from the Joint Comprehensive Programme of Action (JCPOA), the Iran nuclear deal signed by P5+Germany. That allowed Iran to escalate its nuclear enrichment. Meanwhile, the UAE increased its commercial, technological and military engagement with Israel.After the October 7, 2023, attacks on Israel and the brutal Israeli retaliation against Gaza civilians, Arab countries' membership of the Abraham Accords became questionable. Neither the UAE nor Bahrain withdrew. Late Iranian Supreme Leader Ali Khamenei called the UAE a "traitor to Arab states and to Palestine", declaring that those hosting Zionists were living in "glasshouses".

The UAE and Bahrain ignored these warnings. Once the US and Israel attacked Iran on February 28, the Iranian Supreme Leader's "glasshouses" prediction came true. The Gulf Cooperation Council (GCC) has split into three groups, each aligned with the US. One group comprises Saudi Arabia, Egypt, Pakistan and Turkey. Qatar is attempting to be neutral. And then there is the UAE, stuck with the Israel-US axis. India favours the last two.

The Washinton Institute for Near East's 2023 poll revealed that 96% of the Saudis supported severing ties with Israel. The Saudi ruling family, running a country with a population of over 35 million, is more responsive to popular sentiments. The UAE's nearly 11-million population has only one million locals. Economic and financial benefits are supposed to keep locals appeased. The 2011 Arab Spring uprisings, which ousted the rulers

of Libya, Algeria and Egypt, frightened the Gulf ruling families. When the Muslim Brotherhood assumed power in Egypt, the Gulf rulers, especially Emiratis, panicked. Subsequently, they became obsessed with countering the Brotherhood and Islamists in the Arab world.The UAE's interventions to support factions in South Yemen, Somaliland, Sudan and Libya were basically focused on containing perceived radical Islam. Saudis and Emiratis initially cooperated but eventually split. Saudis supported old regimes, while the UAE began backing factions. Israel also began using the cover of the UAE to launch intrusions, especially along the Red Sea. Iran-backed Houthis in Yemen opposed the often divided forces backed by the UAE and Saudi Arabia.

Former US President Barack Obama claimed that he rejected the same plan to attack Iran which Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu successfully sold to President Trump. Perhaps PM Modi, who visited Israel days before the attacks on Iran, and the UAE President were similarly misled. Israel's four-stage operation started with the Iranian Supreme Leader's assassination, followed by neutralisation of Iran's missile-launch capability. A popular uprising was then expected, leading eventually to a secular government. This regime change sequence failed miserably. Instead, the Strait of Hormuz became a new obstacle.Despite the UAE's discomfort over being geographically stuck between Iran and Saudi Arabia, it hosted about 8,000 Iranian companies. It also provided Iran a trade outlet, bypassing US sanctions, lifting trade to $29.2 billion in 2025. But President Sheikh Mohamed bin Zayed wanted the UAE's strategic reach to match its wealth. The Emirati sovereign fund exceeds that of Saudi Arabia. Israel was seen as enabling this expanded influence to deter Iran and rival Saudi Arabia. Instead, Israel has dragged the UAE into the current impasse.

Even the US has abandoned talk of Iranian regime change. Trump, who is now insistent that Iran should not have nuclear weapons, is keen to restore navigational freedom in the Strait of Hormuz. If sanctions on Iran are lifted and its energy exports freed, will it normalise Iran-UAE relations? Without that deal, Dubai cannot revert to past success. Netanyahu complicated matters by revealing his secret meeting with the UAE President in Abu Dhabi in March. Does Netanyahu, by damaging the Emirati President's standing, hope to ensure that the UAE does not abandon the Abraham Accords or cut a deal with GCC neighbours or even Iran?

PM Modi's visit was aimed more at boosting the UAE President's morale than creating new strategic openings. The proposed $5-billion investment in Indian infrastructure mostly goes to a private housing development company. The move to enhance Indian strategic petroleum reserves by 30 million barrels is welcome, but it merely implements old proposals. The LPG supply would depend on the Iran-US peace deal.

Considering the fractured GCC and Pakistan's defence agreement with the Saudis, India is left with the Abraham Accords-compliant faction or "neutral" nations like Qatar. Notably, during his visit to Delhi last week, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi suggested that the Chabahar port awaited India.

Halwara takes off: Aviation ambitions face test of sustainability

For Ludhiana, the Delhi-Halwara connection is a gateway to national and global markets

AFTER decades of waiting, missed deadlines and political promises, the sight of the first commercial flight landing at Halwara airport carries emotional and economic significance for Punjab. For Ludhiana, the Delhi-Halwara connection is a gateway to national and global markets. The launch has been greeted with excitement across central Punjab. Administrative authorities arranged transport for passengers, political leaders rushed to claim credit and tickets reportedly saw brisk demand even before operations formally began. That enthusiasm is understandable. Ludhiana's exporters, industrialists and entrepreneurs have long complained that dependence on Chandigarh and Amritsar slowed business mobility and increased logistics costs.Halwara also arrives at an important moment. The Centre recently expanded the UDAN regional connectivity scheme with an outlay of nearly Rs 28,840 crore, compared to the original Rs 4,500 crore allocation. The programme seeks to develop 100 new airports and airstrips. However, regional connectivity remains uneven. North India accounts for nearly 30% of the country's passenger traffic, but many

smaller airports continue to struggle with weak demand and irregular flights.

That is why Halwara's success cannot be taken for granted. Many airports inaugurated with fanfare have become underutilised later. Infrastructure without sustained airline operations quickly turns into an expensive symbol rather than an economic asset. Still, Halwara possesses some advantages. The airport's terminal, developed by expanding the Air Force base, can handle 300 passengers at a time, while Air India has begun operations with two daily flights to Delhi. Ludhiana's industrial ecosystem gives the airport a natural passenger base that many UDAN airports never had. But the real test begins after the inaugural applause fades. Connectivity must become reliable, affordable and commercially sustainable. Cargo handling, last-mile transport and route expansion will determine whether Halwara truly transforms Punjab's economy. The state must ensure the runway remains busy.

Faithline | Grace of Skanda

Gods are in our very marrow, and we should accept that with gratitude and respect. And since the gods are some of the most beautiful intuitions of mankind, one could eternally welcome them in their hearts and carry them forward in the form of knowledge

Adhika Skanda Sashti falls on May 21, and brings sweet thoughts of Murugan, meaning 'the beautiful one' in Tamil. The main Skanda Sashti occurs in October or November and is celebrated as a major festival in Tamil Nadu and across the Tamil diaspora. But there are also monthly remembrances of his feat of defeating the asura Surapadman and his brothers to restore cosmic balance and peace on EarthMurugan's various lilas, or sacred games, have shaped the contours of Tamil culture since ancient times, and he remains an abiding source of spiritual strength, emotional security and courage in adversity for many. After all, whose son is he? Besides his own powerful shakti, he additionally combines the strength and blessings of his divine parents and elder brother in his radiant self. Even in Delhi, his abode, the Uttara Swami Malai or Malai Mandir, affords a heartening glimpse of 'gopura darshan' and typically southern red-and-white base stripes as one passes by. It elicits the instinctive murmur of the Shadakshari or six-syllable, Murugan mantra 'Om Saravana Bhava', with Om as the general mantra prefix.

Murugan's six-temple circuit in Tamil Nadu is like an energy grid holding the land together, and it has an old tradition of kavadiyas who wear green dhotis and walk in peaceful, orderly files from temple to temple. The six temples are Tiruppurankunram (kunram means hill, where Murugan temples are usually built), Tiruchendur by the sea, Palani, Swami Malai, Tiruttani and Pazhamudhirsolai. His consorts, the Tamil beauty Valli (possibly the oldest love story of the Tamil land) and Lord Indra's daughter Deivanai, represent his Ichha Shakti and Kriya Shakti, and also symbolically unite North and South into one force-field of energy.

My father's ancestral temple is Tiruttani, and I was taken there as a child for mottai or mundan, the ritual shaving of the head. Going back as an adult merely out of cultural curiosity at the height of my 'Left-liberal Khan Market gang' phase, I nevertheless felt such a strong tug of attachment and such an overwhelming sense of having come home that I was taken aback. I see it now as Murugan's grace. It dawned on me that some earthly songs go deep, that the gods are in our very marrow, and we should accept that with gratitude and respect, and not be led unnecessarily astray.Perhaps it's also because the things we hear that 'speak to us' can subconsciously form deep layers of identity. I was exposed to world music from childhood because my parents had very eclectic tastes and bought all kinds of records that they played all the time. There was Carnatic, Hindustani and Western classical, old Tamil and Hindi film songs, Bengali geet and Urdu ghazals, Western pop and musicals, you name it.

But in this garden of sound, Murugan bhakti songs bloomed like sudden, sweet grace notes of malli (jasmine). So, along with all that other music, I listened to various melodic compositions on Murugan. They were in Tamil, and I found them very powerful and energising, renewing your spirit each time with their good vibrations. They are all available online today, rendered by various gifted singers.They range from the immortal 14th-century Tiruppugazh by the reformed rake Arunagirinathar, the 19th-century Kanda Sashti Kavacham, composed by Devaraya Swamigal, which is a hypnotic power chant in mellifluous Tamil with built-in bijaksharas ('seed syllables' valued as distilled mantras), to the thrilling 20th-century devotional songs by T N Soundararajan. I was also taken to Bombay's Aurora theatre on Sunday mornings to see the then-powerful genre of Tamil devotional films, which featured unforgettable songs with moving lyrics. So, along with English films like The Sound of Music, The Singing Nun and The Man Who Knew Too Much with its evergreen song 'Que sera, sera', I was lucky enough to get a regular dose of bhakti films in my childhood.The biggest take-home from all this was the electrifying realisation that 'being Indian' was like being given a giant box of chocolates, an akshayapatram of many wonderful and delicious things. That you were not forced to eat only one kind, that it was possible to have it all. All.

And since the gods are some of the most beautiful intuitions of mankind, you could rightfully, honourably and openly have the gods, for they are not going anywhere. This is their home, as much and even more than it is yours and mine, for you and I will pass away, but they have been here for millenniums.The only gods still around from ancient times are those that live eternally in our hearts and in our land, testimony to the master craftsmen and artisans who wrought their images and temples, and to the poets who sang of them, whereas the gods of other ancient civilisations have mostly vanished into museums. Saying which, I realise that I echo an ancient promise. That of Sivaperuman (Lord Shiva) at Chidambaram, where he promised to dance eternally "there and in the hearts of mankind" as Nataraja.

ICICI Bank hikes debit card DCC fee from 1% to 3.5%: What it means

New Delhi.(Agency)

If you often use your debit card for international spending or online purchases linked to foreign merchants, your transactions could soon become more expensive. ICICI Bank has informed customers that it will revise the Dynamic Currency Conversion (DCC) fee on debit cards from June 21, 2026. The charge will rise sharply from the current 1% of the transaction amount to 3.5%.

WHAT IS CHANGING?

The revised DCC fee will apply to certain debit card transactions carried out in Indian rupees under specific situations. This includes purchases made in Indian currency at international locations or payments made in India where the merchant is registered in a foreign country.

In simple terms, even if you are paying in rupees, the extra charge may apply if the transaction is processed through a foreign merchant network.

The bank informed customers about the revision through an official communication, stating that the updated fee structure will come into effect from June 21.

WHAT IS DYNAMIC CURRENCY CONVERSION?

Dynamic Currency Conversion, commonly called DCC, allows customers to pay in their home currency instead of the local currency while making international transactions.

For example, if you are shopping abroad or paying a foreign website, you may sometimes see an option to pay directly in Indian rupees instead of dollars or another foreign currency.

Parle Industries shares jump 5% after PM Modi gifts Melody to Italy PM Giorgia Meloni

HYDERABAD.(Agency)

Parle Industries shares rose sharply on Tuesday after Prime Minister Narendra Modi gifted a pack of Melody toffees to Italian Prime Minister Giorgia Meloni during his visit to Italy, triggering a fresh social media frenzy around the popular "Melodi" trend. Shares of Parle Industries jumped 5% intraday to Rs 5.25. The stock was also up nearly 7% over the past one week.

However, despite today's rise, the stock remains under pressure over the longer term. Parle Industries shares are still down around 41% in three months, 46% in six months and over 68% in the past one year.

The rally came after a light-hearted video featuring PM Modi and Italy PM Meloni went viral online.

In the clip shared on social media, PM Modi was seen gifting a packet of Melody candies to Meloni, seemingly playing on the viral "#Melodi" phrase that internet users often use while referring to the two leaders together.

Meloni later shared the video on X and wrote, "Thank you for the gift." In the video, she was also heard saying, "He gifted... a very, very good toffee," after which both leaders laughed. The moment quickly caught attention online, with the clip gathering close to a million views within a short span along with thousands of reactions and comments.

Banks may soon have to share more details on risks and financial health, says RBI

NEW DELHI.(Agency)

The Reserve Bank of India (RBI) wants banks to become more transparent about their financial health. In a move aimed at giving customers, investors and market participants a clearer picture of how banks manage risks, the central bank has proposed new disclosure rules under Basel III norms. If implemented, banks may soon have to publish more detailed information about their capital strength, liquidity position and risk exposure every quarter in a standard format.

WHAT HAS RBI PROPOSED?

On Tuesday, the RBI released a draft circular proposing a revised disclosure framework for banks under Basel Pillar 3 norms.

Under the proposal, banks will be required to publish more detailed information on important financial measures such as capital adequacy, leverage, liquidity and risks. The idea is to improve transparency and strengthen market discipline.

The central bank said lenders would need to make quarterly disclosures in a common format so that information becomes easier to compare across banks.

WHAT KIND OF INFORMATION WILL BANKS HAVE TO SHARE?

If the proposal comes into force, banks will have to disclose key financial indicators, including Common Equity Tier 1 (CET1) capital, total capital, risk-weighted assets (RWAs), leverage ratio, liquidity coverage ratio (LCR) and net stable funding ratio (NSFR). In simple terms, these numbers help explain whether a bank has enough financial strength to absorb shocks, manage risks and meet its funding needs. Banks will also need to explain major changes in these figures from one quarter to another and the reasons behind such movements.

Falling rupee isn't trousers, doesn't need pulling up. But is it revealing too much?

The falling rupee needs no support at the moment, and foreign exchange reserves shouldn't be burnt. However, the falling rupee might be pointing to a deeper investment problem. Everything explained here in layman's terms.

New Delhi.(Agency)

It's trousers that have levels— the retro high-rise, the classic mid-waist or the bold low-waist. For currencies, there's no fundamentally virtuous level. On a downhill roll, the Indian rupee touched a lifetime low of 96.81 against the US dollar on Wednesday, and experts believe it could slide further. While it might be a tempting thought, a falling rupee, unlike a pair of trousers, doesn't need pulling up. Not at least now. However, the rupee's weakening often becomes an emotive and political issue.

The world is reeling due to the war in the Middle East that began on February 28 with Israeli and American airstrikes on Iran. India, which depends on energy imports, has been particularly hit. India consumes around 5.5 barrels of crude daily, and every barrel of crude is extracting additional dollars.

At such times, politics takes precedence over policy. The Congress and other Opposition parties are out with a bazooka, attacking the BJP-led NDA government over the rupee that seems to be on Ozempic. It is the Reserve Bank of India (RBI) which intervenes during currency volatility, using the country's foreign exchange (forex) reserve. India's war chest is adequately stocked as of now with $697 billion.

"Presently the market perception is that the RBI would let the rupee find its own level because there is an advantage for exports and also a natural barrier to imports," Madan Sabnavis, Bank of Baroda Chief Economist and author, told India Today Digital. Global trade is done in US dollars, and countries keep adequate

reserves of greenbacks for any contingency. Experts are suggesting that it is best that the RBI doesn't burn valuable forex to shore up the rupee, allowing market forces to determine its value.

"India's close to $700 billion in foreign exchange reserves will not run out because of higher imports. The only way reserves get depleted is if RBI decides to sell foreign exchange reserves to support the rupee," wrote Gita Gopinath, Harvard University economist and former deputy managing director of the IMF, in an op-ed in The Times of India. The piece was titled 'Let The Rupee Do Its Work'. A weaker rupee makes Indian exports competitive in the international market. But for India, which imports more than it exports, a weak rupee leads to domestic price rise. That's when the RBI steps in to control inflation.

Rupee hits record low, inches closer to 97 against US dollar

New Delhi.(Agency)

The rupee weakened to a record low of 96.88 against the US dollar on Wednesday, pressured by surging US bond yields, elevated crude oil prices and persistent strength in the dollar, as investors turned cautious on emerging-market assets.

The sharp fall in the domestic currency comes amid mounting concerns that global interest rates could remain elevated for longer, tightening liquidity conditions and triggering fresh capital outflows from riskier markets.

The yield on the US 30-year Treasury climbed to 5.18%, approaching levels last seen before the 2008 global financial crisis, after investors reassessed expectations around US monetary policy in the face of sticky inflation and geopolitical tensions linked to the Iran conflict. The spike in Treasury yields strengthened the dollar further, putting renewed pressure on emerging-market currencies, including the rupee.

Why is the rupee falling?

Analysts said the rupee is currently facing pressure from multiple global

triggers, including a stronger dollar, rising US yields, expensive crude oil and persistent demand for dollars from importers.

Brent crude continued to trade above $110 per barrel, raising concerns over India's import bill, inflation trajectory and current account deficit. Since India imports a majority of its crude oil requirements, sustained high oil prices tend to increase dollar outflows and weaken the domestic currency.

The rupee had weakened to an intraday low of 96.61 in the previous session before settling at 96.54, weighed down by importer dollar demand and weakness across regional currencies. Rajesh Palviya, Head of Research at Axis Direct, said rising US bond yields have kept the dollar firm, pushing the rupee to fresh record lows and adding pressure on broader emerging-market sentiment. "Rising US bond yields also kept the dollar firm, pushing the Indian rupee to fresh record lows against the greenback and adding pressure on emerging-market sentiment," Palviya said.

Sensex opens 600 points lower, Nifty below 23,500; Tata Steel falls 2%

New Delhi.(Agency)

Benchmark stock market indices opened lower on Wednesday, triggered by uncertainty in the West Asia war and the falling rupee. The BSE Sensex fell 389.19 points, or 0.52%, to 74,811.66 in early trade, while the NSE Nifty50 dropped 107.90 points, or 0.46%, to 23,510.10 as of 9:39 am.

Dr VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said that globally stock markets are facing a headwind from rising bond yields.

"In US, the 10-year is yield is at 4.66% and the 30 - year yield has spiked to 5.19% – the highest level in the last 22 years. This is a red flag to equity markets. With the risk-free return at such high levels, the appetite for risky equity should decline. This is more valid in the case of highly valued AI stocks. But then markets have an ability to surprise and, therefore, the correction need not happen at a time when everyone expects," he added.

After the opening bell, Sun Pharmaceutical Industries Ltd led the Sensex gainers, rising 0.20%. It was followed by Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, which gained 0.09%. Bharat Electronics Ltd saw the sharpest fall, dropping 3.04%. Tata Steel Ltd declined 2.65%, Eternal Ltd slipped 1.58%, UltraTech Cement Ltd was down 1.22%, and State Bank of India Ltd fell 1.04% in early trade. "In India the market headwind comes from macro concerns. In FY 27 GDP growth will be lower at around 6% and inflation can be higher at about 5.5%. It appears that the market has already discounted this," said Vijaykumar. "Even during market weakness, there will be good appetite for promising growth stocks. As a measure of abundant caution investors should give priority to value stocks which are available at fair valuations now. These are testing times. Patience is the key to success," he added.

Wait 5 years for gratuity or take the pay hike? Here's what Indian workers said

New Delhi.(Agency)

"Risk toh Spider-Man ko bhi lena padta hai" ("Even Spider-Man has to take risks"), says Ranbir Kapoor in Rocket Singh: Salesman of the Year. But what if the 'risk' is not about chasing dreams, but resigning from a job just months before gratuity lands in your account?

Imagine this: you are four months away from completing five years at your company when a recruiter calls with a tempting offer, i.e., better pay, bigger role, shinier title. Exciting? Of course. But there is a catch. Leave too soon, and you could miss out on gratuity — a lump-sum benefit paid when employment ends, which employees can generally claim only after completing five years of continuous service in most cases. For lakhs of salaried Indians, this is more than a workplace dilemma. It is a quiet calculation made somewhere between disappointing appraisals, rising EMIs and tempting LinkedIn messages: stay for guaranteed money or leave for a

bigger opportunity?

Curious about what people actually choose, I spoke to professionals across industries, and their answers turned out to be far more emotional, practical and divided than I expected.

'I MISSED GRATUITY ONCE — AND HONESTLY, IT HURT'

The first person I spoke to was Kush Sharma, a working professional from Delhi. His response felt instantly familiar — the kind many mid-career professionals quietly wrestle with. Kush admitted he had already faced this crossroads once. He left a job before completing five years because a better opportunity came along, but the decision came with regret.

"I did feel bad about missing out on gratuity. At the end of the day, everyone works for financial growth and stability. Many employees spend 3–4 years in one organisation, gain experience and skills, and then get a better opportunity. It becomes difficult because gratuity is linked to completing five years."

Need PF money fast? EPFO may soon let you withdraw funds through UPI

Labour Minister Mansukh Mandaviya said on Tuesday that the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has completed testing for a facility that would allow members to withdraw their Employees' Provident Fund (EPF) using the UPI payment gateway.

New Delhi.(Agency)

Waiting for your PF money could soon become much faster and easier. Instead of filing claims and waiting days for processing, EPFO subscribers may soon be able to transfer their provident fund money directly to their bank accounts using UPI.

The government says testing for this new feature has already been completed, and if all goes as planned, lakhs of employees could soon access their EPF savings with just a few taps on their phones.

EPFO TESTING UPI-BASED PF WITHDRAWALS

Labour Minister Mansukh Mandaviya said on Tuesday that the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has completed testing for a facility that would allow members to withdraw their Employees' Provident Fund (EPF) using the UPI payment gateway.

Speaking to reporters, the minister said the withdrawn amount will be transferred directly into a subscriber's bank account. The move is part of EPFO's efforts to improve service delivery and make access to funds simpler for members.

At present, EPFO subscribers usually need to file withdrawal claims to access their PF money, a process many find slow and paperwork-heavy.

HOW THE NEW UPI FACILITY MAY WORK

Under the proposed system, a certain portion of an EPF account is expected to

remain frozen, while a large part of the balance could be made available for withdrawal through UPI-linked bank accounts.

Subscribers will reportedly be able to view the amount eligible for withdrawal in their seeded bank accounts. To complete the transfer, members may simply use their linked UPI PIN, adding an extra layer of security to the transaction.

Once the money reaches the bank account, members can use it freely, whether for digital payments, transfers, or cash withdrawals through ATMs.

A BIG RELIEF FOR OVER SEVEN CRORE EPFO MEMBERS

The new system could benefit more than seven crore EPFO members across India. EPFO has reportedly been working to fix software-related issues to ensure the smooth rollout of the facility.

For many salaried employees, quicker access to PF money could prove useful during emergencies or major life events, especially when immediate funds are needed.

Bail under UAPA: Government to seek larger bench review amid conflicting judgments

Delhi Police sought consideration of bail under the UAPA by a larger bench, citing conflicting judicial rulings on the legal standards governing the grant of bail under the anti-terror law.

New Delhi.(Agency)

The Delhi Police has urged the Supreme Court to refer the issue of granting bail in terror cases under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) to a larger bench, citing apparently conflicting rulings by coordinating benches on the legal standard in allowing the relief.Additional Solicitor General SV Raju, appearing for the Delhi Police in the larger conspiracy case linked to the 2020 Delhi riots, made the submission before a bench of Justice Aravind Kumar and Justice PB Varale, which was hearing bail pleas filed by Delhi riots accused Tasleem Ahmed and United Against Hate member Khalid Saifi against the Delhi High Court's refusal to grant them bail.

The development comes as the Supreme Court on Monday, while hearing a separate case, raised questions over the top court's earlier order denying bail to activist Umar Khalid, reiterating that "bail is the rule and jail is the exception" even in cases under the UAPA.

The court observed that a binding precedent relating to prolonged incarceration appeared to have been overlooked in Khalid's case. He has been in jail since 2020 in connection with the alleged larger conspiracy behind the Delhi riots.

ASG Raju requested that the matter be taken up on Wednesday to consider whether it should be referred to a larger bench. He said he required time to examine the Supreme Court's judgment delivered on Monday in Syed Iftikhar Andrabi vs National Investigation Agency concerning bail under the UAPA.On Monday, a bench of Justice BV Nagarathna and Justice Ujjal Bhuyan held that bail remains the rule even in UAPA cases and expressed reservations about earlier rulings that had adopted a narrower approach to granting bail under the law.Justice Bhuyan on Monday specifically questioned the correctness of the rulings in the Khalid case and another UAPA case involving Gurwinder Singh in Punjab. The judgment observed that the denial of bail to Khalid and Imam appeared to have overlooked the three-judge bench ruling in Union of India vs KA Najeeb, which held that prolonged incarceration and the improbability of an early conclusion of trial could justify the grant of bail even in UAPA cases.Justice Bhuyan said, "A judgment rendered by a bench of lesser strength is bound by the law declared by the bench of greater strength. Judicial discipline mandates that such a binding precedent must either be followed or, in case of doubt, be referred to a larger bench. A smaller bench cannot dilute, circumvent or disregard the ratio of a larger bench."

In January, the Supreme Court granted bail to five accused in the Delhi riots larger conspiracy case while denying relief to Khalid and Sharjeel Imam. The remaining accused, including Ahmed and Saifi, subsequently approached the apex court seeking similar relief.

City's chief poll officer meets parties to discuss SIR

New Delhi.(Agency)

Delhi Chief Electoral Officer (CEO) Ashok Kumar on Tuesday held the first meeting with representatives of political parties after the announcement of the special intensive revision (SIR) of electoral rolls, ahead of the exercise's roll-out on June 30.

The party representatives were given a brief on the whole exercise, and their questions were answered. They assured full cooperation for successfully completing the exercise in the city, said an officer of the CEO's office.The emphasis was on ensuring coordination between booth level officers (BLOs) of the poll body and the booth level agents (BLAs) of the parties for smooth conduct of the SIR, said the Delhi BJP's state coordinator for EC-related affairs.

He said the party had already appointed around 12,600 BLAs for participation in the SIR.

The BLOs will conduct door-to-door surveys from June 30 for verification of Delhi's electoral rolls. They will provide enumeration forms to the voters to be filled and provided to the BLOs for submission.

The CEO office will provide the facility of online submission of completed enumeration forms. BLAs of parties can submit a maximum of 50 filled-up enumeration forms daily, officials said.

Political parties in Delhi have intensified preparations for the SIR by focusing on training their BLAs across nearly 13,000 polling booths in the city.The CEO's office said that the main objective of the SIR is to ensure that "no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll". The exercise will cover all voters aged 18 years and above by the qualifying date, which is October 1.

Door-to-door visits will start from June 30 and conclude on July 29, after which the draft electoral roll will be published on August 5. The final electoral roll after the SIR will be published on October 7.Delhi Congress president Devender Yadav said that the party was well prepared with the deployment of BLAs at each booth to fight any kind of "disturbance" in the SIR.

Capital records season's highest power demand, touches 7,776 MW mark

New Delhi.(Agency)

The capital's peak power demand has witnessed a sharp rise in May 2026 as compared to previous years, reflecting the impact of an intense and early summer.

According to SLDC data, Delhi's peak power demand on Tuesday touched 7,776 MW at 3:30 pm, which marks the highest recorded so far in 2026. On Monday, the city's peak power demand had reached 7,542 MW in the afternoon and further increased to 7,600 MW during the night.

The BSES discoms met the peak power demand of 3,492 MW and 1,683 MW in their respective areas.

Earlier, on April 27, 2026, Delhi's peak power demand had surpassed the 7,000 MW mark for the first time ever in April, touching 7,078 MW at 3:30 pm. However, in comparison, the 7,000 MW level was reached only in May during 2024 and 2025.

Delhi is expected to witness another

significant rise in electricity demand this summer. As per the SLDC projections, as against the all-time high peak demand of 8,656 MW recorded in 2025, Delhi's peak power demand is expected to cross 9,000 MW this year.

BSES has claimed that their discoms are fully geared up to ensure a reliable power supply to more than 53 lakh consumers and nearly 2.25 crore residents across South, West, East and Central Delhi.These arrangements include long-term PPAs, bilateral tie-ups, banking arrangements with other states and deployment of advanced technologies such as AI and ML-based demand forecasting to accurately estimate load and maintain uninterrupted supply. Additionally, around 2,670 MW of green power will play a key role in ensuring reliable electricity supply during the summer months in BSES areas. On the other hand, Tata Power-DDL also supplied the season's peak demand of 2220 MW to date seamlessly.

DGCA officers to inspect Boeing fuel control switch at US facility in June

Flight AIC 132, operating from London Heathrow to Bengaluru on February 2, 2026, was grounded after a malfunction was reported in the switch.

New Delhi.(Agency)

Aviation regulator, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), has directed the inspection of the Fuel Control Switch (FCS) of an Air India Boeing 787-8 aircraft that operated from London Heathrow to Bengaluru by its officers in June at the Boeing facility in the US.

Flight AIC 132, operating from London Heathrow to Bengaluru on February 2, 2026, was grounded after a malfunction was reported in the switch.The Fuel Control Switch in Boeing aircraft came under international scrutiny following the Air India Ahmedabad plane crash on June 12, 2025, in which 260 people were killed. According to investigators, the switch had moved to the 'OFF' position after take-off, cutting off fuel supply to the aircraft.

An official release from the Aviation Ministry said the aircraft was grounded after an entry in the Pilot Defect Report stated that the left FCS "slips from RUN to CUT OFF when pushed slightly and does not lock positively in its selected position".

Based on recommendations from the Original Equipment Manufacturer, Air India conducted a preliminary inspection and functional testing of the switch in Bengaluru in the presence of Directorate General of Civil Aviation officers.

"Upon review of the inspection results and evidence provided, OEM concluded that the Fuel Control Switch was mechanically functioning as designed and considered the unit serviceable," the release said.

The DGCA India, as part of continued airworthiness of the involved Fuel Control Switch, has directed for their inspection at OEM facility in presence of its officers, it added.

International scrutiny after Ahmedabad crash

The Fuel Control Switch in Boeing aircraft came under global scrutiny following the Air India Ahmedabad plane crash on June 12, 2025, in which 260 people were killed. According to investigators, the switch had moved to 'OFF' position after take-off, cutting off fuel supply.

Technical issues disrupt Class XII re-evaluation process, date extended

New Delhi.(Agency)

Frustrated students spent hours refreshing web pages, waiting for OTPs and repeatedly logging into the CBSE portal on Tuesday as the Board opened its Class 12 re-evaluation and answer-sheet verification process for 2026. What many expected to be a quick application process turned into a stressful experience because of slow-loading pages and frequent portal glitches.

Following technical issues faced by several students, the Central Board of Secondary Education on Tuesday evening issued a circular extending the dates for re-evaluation.

"It is hereby informed to all stakeholders that due to a technical problem encountered on the CBSE website for post-verification facilities, and to ensure sufficient time for students, the last date for

obtaining scanned copies of evaluated answer books has been extended from May 22 to May 23, 2026," the CBSE statement read.

With college admissions and cut-offs already creating pressure among students, the technical glitches added to their anxiety. Several students complained that the portal kept freezing midway, while others said even basic steps such as captcha verification and page loading were taking unusually long.

"Today's re-evaluation portal opening was honestly quite frustrating. The website kept hanging and even the captcha took forever to load, which made the whole process unnecessarily time-consuming," said Ishanvi Bagga, a Class 12 student of Mount Carmel School.Many students said they spent nearly their entire morning trying to access the portal properly.

Pharmacists, commercial vehicle operators to go on strike on financial concern

New Delhi.(Agency)

The capital is set to witness back-to-back protests this week as chemists and commercial vehicle operators have announced separate strikes over regulatory and financial concerns.The All India Organisation of Chemists and Druggists has announced a nationwide pharmacy strike on May 20 opposing the rapid and unregulated expansion of e-pharmacies and online medicine delivery services.

Meanwhile, commercial vehicle unions in Delhi-NCR have also announced a three-day strike from May 21 to May 23. Drivers are demanding an immediate hike in auto and taxi fares to cope with rising petrol, diesel and CNG prices.

A member of Indira Pharmacy said the nationwide pharmacy strike is mainly driven by the growing shift of customers towards online medicine platforms offering heavy discounts.

"People are choosing online apps because medicines are available at cheaper rates than at physical stores. Small pharmacies are struggling to compete with these discounts," the member said, highlighting concerns over the survival of traditional chemist shops.

Rai Medios from Mahavir Enclave in Dwarka said, "Online platforms offer heavy discounts that local pharmacies cannot match, making it difficult for small chemist shops to survive. We support the strike and our store will remain closed on the strike day."

Echoing a similar concern, Ali Haider, a pharmacist who has been working in the sector for the past eight years, said, "If small chemist shops shut down, people may realise their importance only during emergencies, when nearby pharmacies are the quickest source of medicines. The government should recognise this."

Delhi's three landfill sites await processing of 44 LMT legacy waste

New Delhi.(Agency)

With a little over six months left before the deadline to flatten two of Delhi's three landfill mountains, the city still has nearly 44 lakh metric tonnes (LMT) of legacy waste waiting to be processed at the Bhalswa and Okhla landfill sites.

A few days ago, Delhi Mayor Pravesh Wahi said that the Municipal Corporation of Delhi aims to clear the Bhalswa and Okhla landfill sites by the end of this year, while the complete remediation of the Ghazipur landfill will be completed by the end of 2027. Wahi said that the civic body is continuously carrying out biomining and remediation work at the three legacy waste sites.

Official progress figures accessed by the newspaper show that the Bhalswa landfill, targeted to be flattened by December 2026, still has 26 lakh metric tonnes of waste remaining.

So far, authorities have reclaimed 35 acres of land, but the site continues to carry one of the city's largest waste burdens despite the deployment of 24 trommel machines for processing old garbage.

Meanwhile, the situation at the Okhla landfill, for which the earlier July 2026 completion target has now been extended, appears comparatively better but still remains far from completion. Around 18 LMT of waste is yet to be cleared from the site. Official figures show that nearly 25 acres have already been cleared through biomining operations, with 18 trommels currently deployed on the ground.

Taken together, the two landfill sites still hold 44 lakh metric tonnes of legacy waste— equivalent to millions of tonnes

of decades-old mixed garbage that must be excavated, segregated and processed before the deadlines can be met.

The figures also indicate contrasting trajectories at the two sites. Bhalswa landfill has reclaimed more land than Okhla but still carries a significantly larger waste burden. Okhla landfill, however, has less waste remaining and more land recovered relative to the waste still left to be processed.

The landfill-flattening exercise forms part of Delhi's broader push to eliminate the city's infamous garbage mountains through biomining. In this process, old waste is excavated and passed through trommels—large rotating screening machines that separate soil-like material, recyclable components and fuel.

However, the remaining volume continues to raise questions about the pace at which the work can be completed.The third landfill, Ghazipur, has a later deadline of December 2027, with 67 LMT of waste still remaining, making it Delhi's biggest unfinished waste-remediation challenge. For now, however, the focus is likely to remain on whether Bhalswa and Okhla can clear the tens of lakh tonnes of waste still standing between them and their promised flattening targets.

NEWS BOX

5.9-magnitude earthquake hits Japan's Kagoshima, no tsunami warning for now

World. (Agency)

A powerful 5.9-magnitude earthquake struck Kagoshima region of southern Japan on Wednesday, shaking buildings and triggering panic among residents. The tremors were felt across several parts of the area, though authorities were still assessing the situation.No tsunami warning had

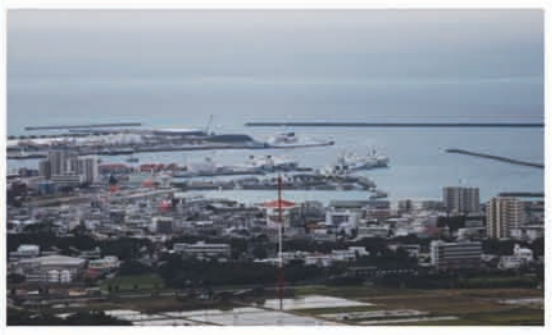

been issued immediately after the quake, and there were no initial reports of casualties or major damage.According to Japanese media, the Japan Meteorological Agency said "the magnitude 5.9 quake struck near Okinawa Main Island, and had an intensity of upper 5 on the Japanese scale of 0 to 7 in the hardest-hit areas," adding, "There is no risk of tsunami".

Japan, one of the world's most earthquake-prone countries, frequently experiences seismic activity due to its location along the Pacific Ring of Fire.The latest seismic activity comes just four days after another strong earthquake struck off the eastern coast of Japan's main island of Honshu, briefly disrupting train services and prompting emergency alerts across parts of the Tohoku region. That quake also caused no tsunami threat or immediate reports of casualties or significant damage.

Mosque security guard hailed as hero for saving 140 children in San Diego attack

World.(Agency)

A security guard killed in the shooting at the Islamic Centre of San Diego has been hailed as a hero for helping save about 140 schoolchildren by confronting two teenage gunmen during the attack, authorities said on Tuesday.San Diego police identified the guard as Amin Abdullah, also known as Brian Climax. According to Police Chief Scott Wahl, Abdullah exchanged gunfire with the suspects in the mosque parking lot on Monday, delaying and distracting them as they attempted to move deeper into the complex.

Abdullah was fatally shot during the confrontation, along with two other men who authorities said helped draw the attackers away from crowded areas of the mosque while officers rushed to the scene.Police said Abdullah also transmitted the emergency radio call that triggered lockdown procedures inside the mosque complex, allowing worshippers and children attending classes at the adjacent Bright Horizon Academy to shelter behind locked doors.

"His actions, without a doubt, delayed, distracted and ultimately deterred those two individuals from gaining access to the greater areas of the mosque where as many as 140 kids were within 15 feet of these suspects," Wahl told reporters, according to Reuters.The two suspects, identified by officials as Caleb Vasquez, 18, and Cain Clark, 17, fled the mosque complex by car shortly after the shooting. Police later found both teenagers dead inside the vehicle several blocks away from what investigators believe were self-inflicted gunshot wounds.

Taha Hassane, imam and director of the mosque, described the three victims as "our martyrs and our heroes."

Authorities said the attack is being investigated as a hate crime. FBI officials confirmed that one of the suspects left behind a manifesto, while investigators also discovered anti-Islamic writings inside a vehicle connected to the pair.

India's Nuclear Sector Opens to the World: How the SHANTI Act Is Rewriting History

World.(Agency)

A 20-member U.S. nuclear industry delegation met Union Minister of State for Science and Technology Dr Jitendra Singh on Monday to explore investment opportunities in India's nuclear sector, months after the SHANTI Act overhauled the country's six-decade-old nuclear laws.

The delegation, comprising representatives from the Nuclear Energy Institute and the U.S.-India Strategic Partnership Forum, discussed manufacturing partnerships, supply chain integration and technology cooperation under India's Nuclear Energy Mission.

Singh said India aims to scale nuclear power capacity from 8.8 gigawatts to 100 gigawatts by 2047 through a phased expansion strategy, adding that the programme was creating major opportunities for global partnerships in manufacturing, technology cooperation, supply chain integration and advanced research.The estimated market value stands at nearly 300 billion dollars.The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act, 2025, repeals the Atomic Energy Act of 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act of 2010, replacing both with a single comprehensive law.

US set up a chessboard with Munir as a pawn years ago. It's playing out now

A chessboard had been laid much earlier. A game had begun even before former Pakistan PM Imran Khan realised it, and Asim Munir took over as the army chief. The US moved the pieces for a regime change in Pakistan. It now has a strategically placed player as the Middle East burns.

DAKAR. (Agency)

Pakistan is where anything can happen. It's also a place where everything happens for a reason. Nothing happens in isolation. Governments fall, generals rise, prime ministers turn into prisoners and prisoners into symbols of resistance. Former Pakistan PM Imran Khan's rise to power, his anti-American posturing, his "absolutely not" doctrine, his Moscow visit on the very day Russia invaded Ukraine, the all-out war between him and the military establishment, his fall from grace, imprisonment, and now the rise of Field Marshal Asim Munir as arguably the most powerful man Pakistan has seen are all connected.The chain of events in Pakistan since the early 2022s led to the outcome which was planned. It all seemed orchestrated by a king and his pawn, according to a report by American outlet Drop Site News on May 18.The Drop Site News report now appears to fit all the events mentioned above together like a jigsaw puzzle.

The chessboard had been laid much earlier. The game had already begun long before Imran Khan realised it. And in the game reminiscent of the "Great" one from the Cold War-era, Asim Munir was not the king, but the pawn being moved across the board. Washington watched, nudged and orchestrated events in Pakistan from a distance.While headlines on the report's

revelations focused largely on Imran Khan's removal from the prime minister's post through an internationally-backed plot. But another angle, perhaps even more intriguing, is that the man who today sits at the pinnacle of Pakistan's power structure, Asim Munir, was central to the bigger rouge geopolitical rearrangement. The report also noted that Pakistan, in pursuit of its "strategic depth", continues to oscillate between dependence and bargaining at high tables in Washington, Beijing, Riyadh and Rawalpindi, while behaving like a sovereign nation.

At the heart of it all is the cipher case. It is a classified diplomatic cable sent in March 2022, by Pakistan's then ambassador to Washington, Assad Majeed Khan, to Islamabad's Foreign Ministry. The cable quoted senior US official Donald Lu as allegedly saying that "all will be forgiven in Washington" if the no-confidence vote against Imran Khan succeeded. That single line would go on to become the political nuclear weapon around which Imran Khan would base his anti-American narrative, much to the displeasure of the establishment in Rawalpindi.

Moment US cargo plane lost engine before fiery crash that killed 15

World.(Agency)

New surveillance footage released by the National Transportation Safety Board (NTSB) shows the precise moment UPS Airlines Flight 2976 lost its left engine and pylon during takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport, offering investigators their clearest visual evidence yet of the catastrophic November 2025 crash that killed 15 people, New York Post reported.The newly released CCTV video captures the cargo aircraft accelerating down the runway before lifting off.

Seconds later, the left engine and its pylon — the structure attaching the engine to the wing — can be seen tearing away from the aircraft.

In the footage, the detached engine falls toward the ground as the jet continues

climbing briefly, trailing debris, before losing control.oments later, the aircraft disappears from view and a fireball erupts, sending thick black smoke into the sky over Louisville's industrial outskirts.

The aircraft, a 34-year-old McDonnell Douglas MD-11F freighter, had departed for Hawaii on November 4, 2025.The crash happened moments after takeoff, scattering debris over nearly half a mile and igniting a large blaze near the airport.

All three crew members on board died, along with 12 people on the ground. More than 20 others were injured.UPS identified the deceased crew as Captain Richard Wartenberg (57), First Officer Lee Truitt (45), and International Relief Officer Captain Dana Diamond (62).One of the injured on the ground, Alain Rodriguez Colina, later died from his injuries on Christmas Day, raising the death toll to 15.

NTSB PROBES UPS FLIGHT 2976 CRASH

The footage was released as the NTSB opened a two-day hearing in Washington this week to examine why the aircraft lost an engine shortly after departure, a CNN report said.

Small price to pay: Norwegian journalist says Insta, Facebook accounts suspended

World.(Agency)

Norwegian journalist Helle Lyng, who drew attention after attempting to question Prime Minister Narendra Modi during a joint media briefing in Norway, has claimed that her Instagram and Facebook accounts were suspended amid a wave of online backlash.Posting on X, Lyng said she had been unable to access her Instagram account throughout the day before it was suspended. "It is a small prize to pay for press freedom, but I've never experienced it before," she wrote while sharing a screenshot of the alleged suspension notice.

In another post, Lyng informed users trying to contact her through Meta-owned platforms that both her Instagram and Facebook accounts had been suspended. "I have wanted to respond to as many Indians as possible, but my responses will now be delayed. I hope I will get my accounts back," she wrote while tagging Meta.

The controversy began after Lyng attempted to question PM Modi during a joint media interaction with Norway's prime minister. "Why don't you take some questions from the freest press in the world?" she shouted as the Indian prime minister left the room. While it was unclear whether Modi heard the remark, the moment quickly went viral on social media.

Later, Lyng defended her actions on X, saying she did not expect Modi to answer her question. Referring to global press freedom rankings, she wrote that Norway occupies the top spot on the World Press Freedom Index while India ranks 157th. Lyng works for Oslo-based newspaper Dagsavisen.

As the exchange triggered political reactions online, the Indian embassy in Norway invited Lyng to a separate press briefing later in the day. During that interaction, she again raised questions related to India's credibility and human rights record. MEA Secretary (West) Sibi George responded by highlighting India's civilisational history, contributions such as chess and yoga, and the country's Covid vaccine outreach.

The episode also sparked a fierce social media backlash against Lyng, with several users accusing her of being a "foreign plant", "spy" and even a "Chinese proxy", citing some of her earlier articles on China and President Xi Jinping. Others argued that the event was a joint media briefing rather than a formal press conference.As criticism intensified, Lyng issued another clarification on X. "I never thought I would have to write this, but I am not a foreign spy of any sort, sent out by any foreign government. My work is journalism," she said.

Despite the controversy, the incident dramatically boosted Lyng's visibility online. Her X following reportedly surged from fewer than 800 followers before Monday to more than 45,000 within days.

Trump says US could strike Iran again within days as Tehran warns of 'new fronts'

World.(Agency)

Tensions between the United States and Iran escalated sharply on Tuesday after US President Donald Trump said Washington could launch fresh military strikes against Iran within days if ongoing negotiations fail, while Tehran warned it would retaliate by opening "new fronts" against the US.

Speaking at the White House, Trump claimed he had been close to authorising military action before pausing the decision following requests from American allies in the Gulf region."I was about an hour away from making a decision," Trump told reporters, adding that Gulf partners had informed him that negotiations brokered by Pakistan were making progress and requested additional time for diplomacy.

The US President said he agreed to allow "a limited period of time — two or three days, at least" for talks to continue. However, he warned that military action remained on the table.

"It could be Friday, it could be the weekend, it could be early next week," Trump said while discussing the possibility of renewed strikes. "We can't let them have a new nuclear weapon."

Trump also claimed that Iranian leaders were "begging" for a deal, though he did not provide further details.Referring to previous failed negotiations, Trump said the current round of diplomacy appeared different from earlier attempts.We've had periods of time where we had, we thought, pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out. But this is a little bit different," he said.

Meanwhile, Israeli broadcaster Kan TV reported that the United States and Israel had completed joint preparations for a possible resumption of military operations against Iran.

Citing a US security official, the report said, "The United States and Israel are fully coordinated. Neither side will be surprised if a decision is made to resume the war."According to the report, the Israeli military has also strengthened defensive preparations amid fears that growing speculation about renewed conflict could trigger a preemptive Iranian response.

Russian troops secretly trained by China return to fight against Ukraine: Report

World.(Agency)

UChina's armed forces secretly trained about 200 Russian military personnel in China late last year and some have since returned to fight in Ukraine, according to three European intelligence agencies and documents seen by Reuters.While China and Russia have held a number of joint military exercises since Moscow's full-scale invasion of Ukraine in 2022, Beijing has repeatedly stated that it is neutral in the conflict and presents itself as a peace mediator.

The covert training sessions, which predominantly focused on the use of drones, were outlined in a dual-language Russian-Chinese agreement signed by senior Russian and Chinese officers in Beijing on July 2, 2025.The agreement, reviewed by Reuters, said about 200 Russian troops would be trained at military facilities in locations including Beijing and the eastern city of Nanjing. The sources said around this number subsequently trained in China.

The agreement also said hundreds of Chinese troops would undergo training at military facilities in Russia.

By training Russian military personnel at an operational and tactical level who then participate in Ukraine, China is far more directly involved in the war on the European continent than previously known, one intelligence official said.

The Russian and Chinese defence ministries did not respond to requests for comment on the details outlined in this article.

On the Ukraine crisis, China has consistently maintained an objective and impartial stance and worked to promote peace talks, this is consistent and clear and is witnessed by the international community," China's foreign ministry said in a statement to Reuters. "Relevant parties should not deliberately stoke confrontation or shift blame."The intelligence agencies spoke on condition they not be identified in order to discuss sensitive information.European powers, which see Russia as a major security threat, have watched warily at increasingly close relations between Russia and China, the

world's second largest economy and an important European Union trade partner.The two nations announced a "no limits" strategic partnership days before Russia's invasion of Ukraine in 2022 and pledged to conduct military exercises to rehearse coordination between their armed forces. As the West tried to isolate Russia, China provided a lifeline by buying its oil, gas and coal.

Chinese leader Xi Jinping is due to host Russian President Vladimir Putin on Tuesday and Wednesday, less than a week after U.S. President Donald Trump's high-profile visit.

China and Russia have cast Putin's trip - his 25th visit to China - as further evidence of their "all-weather" partnership, even as the West urges Beijing to pressure Moscow into ending its war in Ukraine.

DRONE WARFARE

Drones have proved to be a vital weapon in Ukraine.Both sides use long-range models to attack targets hundreds of miles away, while on the battlefield, smaller drones remote controlled by pilots using first person view equipment (FPV) and armed with explosives dominate the sky, making it hazardous for armoured.

NEWS BOX

Ravindra Jadeja 2.0? Harsh Dubey could be India's next all-format weapon

New Delhi. (Agency)

For more than a decade and a half, Ravindra Jadeja has been the ultimate security blanket for Indian cricket. At 37, he remains a multi-format monster, the kind of foundational player who single-handedly balances an entire starting XI. But logic dictates that the clock is ticking, and India's team management is staring down a massive, existential headache: who actually replaces him?

For years, the blueprint for life after Jadeja seemed simple: Axar Patel. A like-for-like clone down to electric fielding and sharp left-arm orthodox angles. Axar was the natural heir, yet, succession plans rarely survive the reality of form and time. Axar himself is now 32, and a largely forgettable Indian Premier League campaign has exposed the fragility of relying on a single contingency plan.

The future, it turns out, needs to be built now.

Enter Harsh Dubey.

In a decisive move to test the true depth of the domestic circuit, selectors have called up the 23-year-old talent from Nagpur for both the

one-off Test and the three-match ODI series against Afghanistan.

"I am very confident he can fill Ravindra Jadeja's boots," Usman Ghani, head coach of the Vidarbha senior men's cricket team, told India Today. "He has done it for Vidarbha, and he could surely do it for India. What sets him apart isn't just his skill set, but his mentality. He is incredibly strong mentally, and he has been proving that across multiple formats in the domestic circuit."

THE BREAKOUT

Ghani's unwavering faith is rooted in hard data. When Vidarbha lost veteran spinner Aditya Sarwate to Kerala in 2024, a massive vacuum opened at the heart of their bowling attack. A young Dubey was thrust into the role of spearhead. "He was required to step into giant shoes, and he did a splendid job," Ghani says.

Another Banglawash: Pakistan sink to new low despite Rizwan fight in Sylhet Test

NEW DELHI. (Agency)

History has a cruel habit of repeating itself, but for Pakistan cricket, it has begun to feel like an endless loop of humiliation. Two years after being subjected to an unprecedented home whitewash at the hands of Bangladesh, the humiliation was complete on foreign soil. On a humid Wednesday morning at the Sylhet International Cricket Stadium, the final wickets crumbled to seal a comprehensive 78-run victory for the hosts, confirming another historic "Banglawash" with a 2-0 series sweep.

Chasing a mammoth, record-breaking target of 437, Pakistan's fourth-innings resistance ended at 358. On paper, scoring over 350 in the final innings of a subcontinental Test is a commendable feat-a point captain Shan Masood futilely clung to in the post-match ceremony. But in reality, it was a veneer of respectability masking a familiar, structural collapse. The final morning began with an agonising, rain-delayed wait, but once the wet patches dried and play commenced, Bangladesh required less than an hour to dismantle the remaining resistance.

All Pakistani hopes rested squarely on the shoulders of Mohammad Rizwan. Resuming on his overnight score of 75 with Pakistan at 316 for seven, the wicketkeeper-batter played with the grit of a man fully aware that he was standing on a burning deck. He navigated a probing, hostile short-ball spell from Taskin Ahmed early on, surviving an awkward inside edge that narrowly missed his stumps.

Rizwan and Sajid Khan began to score freely, adding 46 runs to the overnight score and bringing the equation down to less than 100 runs. However, left-arm spinner Taijul Islam got the breakthrough, removing Sajid in the 96th over and completing a five-wicket haul.

The definitive, heartbreaking moment for the visitors came when Rizwan, orchestrating a lonely crusade after Sajid's exit, fell just six runs short of a well-deserved century. He poked at a delivery angled across him by Shoriful Islam and was caught at slip cordon.

India's squad vs Afghanistan: Decoding the big snubs, what it means for the future

The squad announcement for the Afghanistan series marks the official blueprint for India's future. While senior pillars remain, the selectors have actively initiated a transition phase, blooding a younger core ahead of the 2027 World Cup cycle.

New Delhi. (Agency)

India's squad announcement for the Afghanistan ODI and Test series was supposed to mark the beginning of two massive journeys.

In ODI cricket, it officially starts India's final year of combinations, experiments and selection calls before the 2027 World Cup in South Africa, while in Tests, it opens what the Shubman Gill-led side will hope becomes a redemption season after a deeply disappointing 2025-26 red-ball cycle. But once the squads dropped, the real conversation quickly shifted towards the names missing rather than the names included.

Rishabh Pant lost both his ODI spot and Test vice-captaincy. Mohammed Shami was not even in the selectors' longer-format thinking any more. Jadeja and Axar were rested together, while even recent ODI centurions Yashasvi Jaiswal and Ruturaj Gaikwad could not force their way into the 50-over squad.

At the same time, India pushed several younger names into the spotlight.

Harsh Dubey earned selection in both formats. Manav Suthar entered the Test setup. Gurnoor Brar received a maiden call-up across formats. Prince Yadav was brought into the ODI squad as another younger fast-bowling option India want to assess ahead of the 2027 World Cup. It was difficult to ignore the larger pattern unfolding underneath the selection meeting. India are not exactly shutting the door on the older core yet. But they are very clearly preparing for what comes next.

"With regard to one-day cricket, we have 15–16 months left to that World Cup. We

want to assess what our options are, particularly keeping in mind the conditions in South Africa, and give exposure to some of the newer guys," India chief selector Ajit Agarkar said.

India ODI squad vs Afghanistan: Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Nitish Reddy, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Prince Yadav, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Harsh Dubey.

India Test squad vs Afghanistan: Shubman Gill (capt), Yashasvi Jaiswal, KL Rahul (vc), Sai Sudharsan, Rishabh Pant, Devdutt Padikkal, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Manav Suthar, Gurnoor Brar, Harsh Dubey, Dhruv Jurel.

PANT'S WHITE-BALL SPOT IS NO LONGER SAFE

Pant's omission felt harsh because it arrived from two directions at once. He was removed as India's Test vice-captain, with KL Rahul stepping into the role under Gill's leadership setup. Then came the bigger surprise, Pant missing entirely from the ODI squad.

But the selectors very carefully separated those two decisions. Agarkar repeatedly stressed that Pant remains one of India's most valuable Test cricketers.

Arsenal crowned Premier League champions: The 22-year wait is finally over

Arsenal are Premier League champions, ending a 22-year drought. Mikel Arteta's side clinched the title after Manchester City's 1-1 draw at Bournemouth, sparking wild celebrations ahead of Sunday's coronation clash at Crystal Palace.

London. (Agency)

The agonising 22-year drought is officially over. Arsenal are the champions of England once again. Mikel Arteta's side secured the club's 14th top-flight league title on Tuesday night after second-placed Manchester City stumbled to a dramatic 1-1 draw away at Bournemouth.

The arithmetic is locked. The Gunners sit an unassailable four points clear at the summit with just one match remaining. What was supposed to be a high-stakes final weekend has transformed into a glorious coronation this Sunday when Arsenal travel to Selhurst Park to face Crystal Palace.

How the Title Was Won: A Tuesday Night Drama

The tension in North London had been building since Monday evening, when Arsenal ground out a gritty 1-0 victory over Burnley at the Emirates Stadium. Kai Havertz proved to be the hero on the night, latching onto a pinpoint assist from Bukayo Saka in the 36th minute to secure the vital three points. The result threw the ultimate

gauntlet down to Manchester City. Pep Guardiola's side travelled to the Vitality Stadium knowing that only a victory on the south coast would suffice to take the title race down to the final day of the campaign.

Instead, they ran into a Bournemouth brick wall.

The hosts took a stunning first-half lead in the 38th minute through Eli Junior Kroupi, sending shockwaves through the footballing world. City piled on the pressure in the second half, throwing everything forward. A stoppage-time equaliser from Erling Haaland in the 90th minute offered a brief glimmer of hope for the visitors, but the final whistle blew mere moments later, mathematically handing Arsenal the silverware.

In a poetic twist of fate, the title was delivered to Arsenal with a massive tactical assist from Bournemouth manager Andoni Iraola, a close childhood friend of Mikel Arteta. Arteta, who had jokingly admitted the previous day that he would be Bournemouth's "biggest fan" for a couple of hours on Tuesday, saw his wishes answered in spectacular fashion.

Can I get a photo? Australia great turns Sooryavanshi fanboy after Jaipur storm

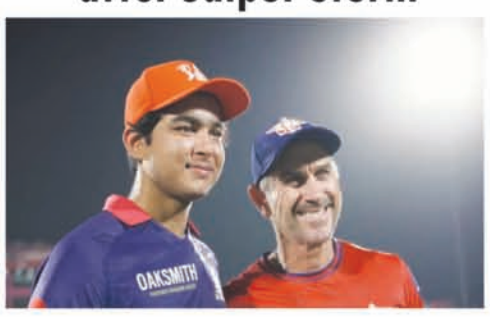

New Delhi. (Agency)

For three and a half decades, Justin Langer has lived his life inside cricket's most unforgiving cauldrons. He has ducked under Shoaib Akhtar bouncers, traded verbal volleys with standard-issue fast-bowling greats, and coached Australia with the kind of intense, unblinking grit that defines the baggy green mythos. He is not a man easily moved to awe.

Yet, on a humid Jaipur evening, the 55-year-old Australian legend found himself reduced to the ultimate modern cricketing condition: becoming a fanboy for a 15-year-old.

As Vaibhav Sooryavanshi stood on the outfield of the Sawai Mansingh Stadium, dutifully churning out platitudes for a standard post-match IPL digital video, a shadow fell over the frame. It was Langer. The Lucknow Super Giants head coach hadn't just stayed back to offer a polite, perfunctory handshake. He wanted a memento.

"Can I get a photo, please?" Langer asked, almost gently, interrupting the recording. The teenager paused, momentarily shedding his status as the tournament's premier destroyer to offer the respectful compliance of a schoolboy. Langer beamed, tucked into the frame, and delivered a parting line that belonged in a time capsule: "I am going to treasure that photo. Good luck for your career. Go well."

It was a vignette that perfectly captured the surreal nature of the Sooryavanshi phenomenon. The Rajasthan Royals prodigy hadn't just beaten LSG with his breathtaking 38-ball 93; he had entirely disarmed them.

PRIVILEGE TO WATCH HIM OUT: LANGER

Hours later, the sheer disbelief had not worn off. Sitting in the press room, Langer's mind was still reeling, trying to contextualise what the IPL was witnessing.

"We've seen it all season, he's the leading run scorer," Langer remarked, shook. "In all my time, I've seen some amazing players in 35 years of cricket. To see a young man bat like that, not just tonight, but throughout the series, is breathtaking."

Vaibhav Sooryavanshi not buying into the hype, its just the start of a long journey

Jaipur. (Agency)

The Indian Premier League (IPL) has long been a launchpad for instant stardom, but few players have seen their stock rise as rapidly as 15-year-old batting sensation Vaibhav Sooryavanshi. On Tuesday night, the teenage opener left the cricket world awestruck at the Sawai Mansingh Stadium, smashing a breathtaking 38-ball 93 to lead Rajasthan Royals to a crucial seven-wicket victory over Lucknow Super Giants (LSG).

Chasing a massive target of 221, Sooryavanshi demolished the LSG bowling attack with 10 towering sixes and seven boundaries. It was an extraordinary exhibition of raw power and hand-eye coordination that even earned him the highest praise from legendary commentator Ian Bishop on air: "He is ready." Yet, despite reclaiming the tournament's Orange Cap with 579 runs and securing an India-A call-up, he remains completely unmoved by the hype

surrounding his name.

CALCULATED CHASE, NOT IMPULSE

What makes Sooryavanshi's knock stand out is how deeply calculated it was. Faced with a steep 221-run mountain, a teenager might normally look to hit his way out of trouble immediately. Instead, the young southpaw showed a level of tactical maturity that completely belies his age, taking his time early on to assess the conditions before launching an all-out assault.

"Nothing much. I was just thinking because I was sitting outside during the bowling innings and the wicket looked good," Sooryavanshi revealed in his post-match interview. "I was thinking that today I shouldn't rush too much at the start, I should take some time and if I bat for a longer period, it's going to help the batter at the other end as well."Even after a quieter start, he reached his half-century in the blink of an eye, eventually going on to plunder 29 runs in a single over against India's fastest bowling asset, Mayank Yadav.

KKR vs MI: Playoff hopes on the line for Kolkata as Mumbai look to crash party

KKR vs MI Preview: Three-time champions Kolkata Knight Riders find themselves in a do-or-die situation as they take on an already-eliminated Mumbai Indians at Eden Gardens on Wednesday, with their IPL 2026 playoff hopes hanging in the balance.

New Delhi. (Agency)

Kolkata Knight Riders have no margin for error left in IPL 2026. With their play-off hopes hanging by a thread, Ajinkya Rahane's side will need a win against an already-eliminated Mumbai Indians at the Eden Gardens on Wednesday to remain alive in the race for the final play-off berth.

A defeat would officially end KKR's campaign for the second successive season under Rahane after their eighth-place finish in 2025, a year after winning the title under Shreyas Iyer. Even a win may not guarantee qualification, with KKR also relying on Punjab Kings slipping up against Lucknow Super Giants later this week.

Defending champions Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already sealed playoff spots, while LSG and MI are out of contention. Punjab Kings, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Delhi Capitals and KKR remain in the fight for the lone remaining place.

KKR IN MUST-WIN SPACE

KKR's qualification equation is simple on paper but complicated in reality. They must win both their remaining matches and hope Punjab Kings lose to LSG. Rajasthan Royals currently hold the clearest path among the chasing teams, and their big win over LSG, powered by Vaibhav Sooryavanshi on Tuesday, has put them ahead.

A defeat on Wednesday will bring the curtains down on KKR's chances.

KKR will regret the way their season began. The Shah Rukh Khan-owned franchise has won five of its last six matches, but the late

surge came after a poor start that left them playing catch-up through most of the campaign. Captain Rahane and coach Abhishek Nayar took time to settle on a stable combination, something marquee overseas signing Cameron Green admitted after KKR's win over Gujarat Titans.

"I think it just took us a while, maybe a bit too long, to figure out the right roles and get the right people in the right positions," Green had said.

Since their first win against Rajasthan Royals, KKR have looked a more settled side. Finn Allen has rediscovered his touch at the top, including a century and a 35-ball 93 in his last three innings. Angkrish Raghuvanshi has continued to impress, while Green has started delivering with both bat and ball after arriving for Rs 25.20 crore at the auction.

Vice-captain Rinku Singh has played his finisher's role consistently, while Sunil Narine remains KKR's biggest weapon with the ball.

Rashmika Mandanna

Calls Cocktail 2 Gang 'Beautiful Mess' As She Shares Photos, Fans Say 'Waiting'

Rashmika Mandanna, Shahid Kapoor and Kriti Sanon's Cocktail 2 is all set to release in theatres on June 19. The makers have recently confirmed that the trailer will be out on May 29. Recently, the musical event was held and actors were seen attending it. Rashmika Mandanna shared photos and called the gang beautiful mess.Taking to her Instagram handle, Rashmika Mandanna shared a series of photos and wrote, "I think this gang with Diya, Kunzee and Ally are just one big beautiful mess together." Fans immediately reacted with heart emojis. One of the fans wrote, "Waiting for this trio." Another wrote, "Waiting for Cocktail 2, All the best Guyss!!"As per an update shared with the media, the trailer of Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, and Kriti Sanon starrer will be released on May 29. The film is scheduled to release in cinemas on June 19, and ahead of it, fans have been waiting quite some time for the trailer of the rom-com. Mashooka features Shahid Kapoor romancing Kriti Sanon in Sicily, Italy, and other picturesque locations. Meanwhile, sung by Arijit Singh, Tujhko is a slow romantic track that focuses on Shahid Kapoor and Rashmika Mandanna's story.

Rashmika Mandanna and Kriti Sanon, in a light-hearted banter, were seen clashing over who was the producer's favourite at 'Cocktail 2'. The fun incident took place during the music launch of 'Cocktail 2', held at a popular hotspot in Mumbai on Sunday night, which was followed by a special media meet and greet session.

The light hearted moment began when Kriti Sanon jokingly welcomed everyone to "my song launch," instantly sparking mock protests from Rashmika Mandanna. During the playful banter, Kriti jokingly said, "First of all, all of you, welcome to my song launch, guys."

Cocktail 2, directed by Homi Adajania, is set to release on June 19, 2026, featuring a fresh cast led by Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna, and Kriti Sanon. Cocktail 2 is positioned as a spiritual sequel to the 2012 hit Cocktail, which starred Saif Ali Khan, Deepika Padukone, and Diana Penty. The film has been shot across multiple locations, including Sicily in Italy and several places in Delhi and North India such as Chhatarpur, Gurugram, and South Delhi. The film is produced by Maddock Films and written by Luv Ranjan.

Sonakshi Sinha

Says She's Now Focused On Doing Roles She Truly Wants: 'I'm Very Grateful'

Bollywood actress Sonakshi Sinha, who is gearing up for the release of her upcoming streaming movie 'System', is looking back at her journey in cinema.The actress spoke with IANS during the promotions of 'System' in Mumbai, and opened up about doing masala films like 'R... Rajkumar' and 'Rowdy Rathore' during the initial phase of her career.Talking about how her choices have changed over the years, Sonakshi told IANS, "I really thoroughly enjoyed myself working on those films. I think at that time, I was also in a time where I was doing a lot of these very colourful and very, so to speak, spicy films. And I enjoyed that too. And I think the work that I'm doing now I enjoyed that too. I think at that point of time, that was what was required from me as an artiste".

She further mentioned, "And now this is what is required from me as an artiste. I want to be that actor that you can put in any film. And I will try to be that. But of course, I've reached a point also where I'm doing only the kind of work that I want to do now. So, it was a good journey for me. I think I had to do those films to kind of land up doing the films that I'm doing today. So, that brought me the audience, that brought me the love and support of so many people. Which is why I'm able to do roles like this today. So, I'm very grateful".Meanwhile, 'System' is a courtroom drama, and sees Sonakshi as a lawyer, and Jyothika as a stenographer. It marks Sonakshi's 1st performance as a lawyer. She essays the role of Neha, a determined young lawyer played by Sonakshi Sinha, taking on a tough challenge from her father (played by Ashutosh Gowariker) to be worthy of a partnership in his firm.Produced by Pammi Baweja, Harman Baweja, and Smitha Baliga, 'System' will drop on May 22 on Prime Video.

Four-Month Pregnant Madhuri Dixit Felt 'Dizzy' Shooting Dola Re Dola For Devdas, Reveals Crew Member

Madhuri Dixit was reportedly four months pregnant while shooting the iconic song Dola Re Dola from Devdas. The revelation was recently made by Rubina Khan, a former crew member of legendary choreographer Saroj Khan, who worked closely on the film's dance sequences.The behind-the-scenes detail has grabbed attention because Dola Re Dola, featuring Madhuri and Aishwarya Rai Bachchan, remains one of Bollywood's most celebrated dance numbers even more than two decades later.

'Dola Re Dola' took 17 days to shoot

Speaking to Bollywood Thikana, Rubina Khan recalled the intense rehearsals and physically demanding shoot behind the famous song from filmmaker Sanjay Leela Bhansali's period drama.

"It took 17 days to shoot that song. Rehearsals happened for at least a month. We rehearsed separately, and the lead actors rehearsed separately," Rubina said.

She then revealed that Madhuri was pregnant during filming and struggled while performing one particular dance step. "There's a step in which Madhuri ma'am turns and sits down. That shot kept happening from 9 am to 10 pm because she was four months pregnant. So, she couldn't turn properly and was feeling dizzy," she added. Rubina also shared that the actress was unwell during the shoot but continued performing without asking for changes. "She also had fever at that time. She struggled a lot," recalled Rubina.

Madhuri refused to change difficult dance steps

Rubina praised Madhuri's discipline and dedication towards Saroj Khan's choreography. According to her, the actress never complained even when the steps became physically exhausting. "She'd never ask for a step to be changed. Whatever Master ji said is set in stone."Rubina further compared Madhuri's attitude to younger actors who sometimes request easier choreography. "Newer artists would still tell Master ji a step is tough and if it can be changed. But Master ji would seldom change a step she suggested.

Who Was Inder Kaur? Know About Punjabi Singer Found Dead In Ludhiana Canal After Alleged Abduction

The body of 29-year-old Punjabi singer and make-up artist Inder Kaur, popularly known as Yashinder Kaur, was recovered from the Neelo canal in Punjab several days after she was reportedly abducted in Ludhiana. She had been missing since May 13, according to PTC Punjab. Her family identified the body after it was found on Tuesday morning, May 19, at around 11 am. Authorities have since sent the body to the Civil Hospital in Samrala for a postmortem examination and completion of legal procedures.

The investigation had intensified earlier this week after the singer's brother, Jotinder Singh, filed a police complaint regarding her disappearance. Acting on his statement, authorities registered an FIR on May 15 against Moga-based Sukhwinder Singh, alias Sukha, and his associate Karamjit Singh. As per the complaint, Inder Kaur had stepped out on the evening of May 13 to purchase groceries in her Ford Figo car, but did not return home. When repeated calls to her went unanswered, her family launched a search before eventually reporting the matter to the police.During the course of the investigation, the family allegedly learned that the singer was acquainted with Sukhwinder Singh, a resident of Bhalur village in Moga district. According to Jotinder Singh, the accused had expressed a desire to marry his sister, but she had reportedly turned down the proposal. The family has alleged that the accused kidnapped the singer at gunpoint before allegedly murdering her over personal animosity stemming from a rejected marriage proposal. As per an ABP report, the complainant also claimed that the prime accused had escaped to Canada following the incident and had only recently returned to Punjab prior to the alleged crime.

Police officials have confirmed that the investigation remains underway, adding that further legal action will be taken based on the outcome of the probe.Born in 1997, Inder Kaur was a Punjab-based singer and make-up artist who had built a growing presence in the Punjabi music industry through her songs, live performances, and social media activity.